

अनुगामिनी

दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु है भारत : पीएम मोदी 3 चिकित्सा-इंजीनियरिंग शिक्षा तमिल में शुरु करना चाहिए : शाह 8

पंचायत चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण सम्पन्न

कई पंचायतों पर हुआ सिक्का उछालकर विजेता का चुनाव

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 12 नवम्बर। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में जिस प्रकार जय (अमिताभ बच्चन) हमेशा अपने दोस्त वीरू (धर्मेन्द्र) के साथ विवादों के निपटारे हेतु सिक्के उछालता था, इसी तरह का नजारा आज सिक्किम के कई जिलों में देखने को मिला जहां पंचायत चुनाव के एक समान वोट प्राप्त उम्मीदवारों में से सिक्का उछाल कर विजेता का चुनाव किया गया। इस प्रकार विजेता का चुनाव राज्य में मंगन, गेजिंग और नामची जिलों के कई वार्डों में हुए।
प्रास जानकारी के अनुसार मंगन जिलान्तर्गत देथांग वार्ड में टॉस के माध्यम से तय नतीजों में थापो भूटिया



को विजेता माना गया। थापो और उनके प्रतिद्वंद्वी को एक समान 78-78 वोट ही मिले जिसके बाद सिक्का उछालकर विजेता का चुनाव हुआ। इसी तरह जिले के फेन्सांग वार्ड में भी सिक्का उछाला गया। वहीं गेजिंग जिले के पांच वार्डों और नामची जिला के में बूमटर वार्ड में भी टॉस के माध्यम से विजेता का फैसला किया गया।
उल्लेखनीय है कि इस बार सिक्किम में हुआ गैर दलीय पंचायत चुनाव पूरे देश के लिए एक उदाहरण था। द्विस्तरीय इस पंचायत चुनाव को कुल प्रतिशत 75.5 मतदान हुआ था। पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं आयी। मतदान के बाद

पवन चामलिंग ने सभी विजयी पंचायत प्रत्याशियों को दी बधाई

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 12 नवम्बर। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) सुप्रियो तथा पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने आज मतों की गिनती के साथ राज्य पंचायत चुनाव के समापन पर सभी को बधाई दी है।
आज यहां अपने एक बयान में एसडीएफ सुप्रियो पवन चामलिंग ने कहा कि मैं पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, किसी

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता के हितों की रक्षा और उनके मुद्दों को उठाने हेतु जिम्मेदारी एवं अधिकार दिया गया है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है।
उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि सिक्किम और यहां के लोगों के हित में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम हों। साथ ही उन्होंने एक नया, खुशहाल और मजबूत



सिक्किम बनाने की दिशा में सभी नये पंचायतों और जिला पंचायतों को बधाई व शुभकामनाएं दीं।

14 से होगा एसयू का दीक्षांत समारोह सप्ताह, तैयारियां तेज

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 12 नवम्बर। सिक्किम विश्वविद्यालय (एसयू) का छठा दीक्षांत समारोह आगामी 18 तथा 20 नवम्बर को आयोजित होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय दीक्षांत सप्ताह के तौर पर आयोजित होने वाले शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक पूरी श्रृंखला के माध्यम से शामिल हो रहा है।
विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि कुलपति अविनाश खरे ने एक छात्र के जीवन की एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि होने वाले दीक्षांत समारोह को यादगार बनाने हेतु इसे एक दीक्षांत सप्ताह के रूप में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। इस दौरान पूरे सप्ताह

अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इसके बाद 15 और 16 नवम्बर को दो फैकल्टी लेक्चर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान नई दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं विद्वान प्रफुल्ल केतकर 'सुराज की यात्रा के लिए स्वराज के विचार पर पुनर्विचार' विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। इस अवसर पर सिक्किम के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ. एमएन शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा वरिष्ठ इतिहासकार, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सदस्य और डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी द्वारा भी 'उपनिवेशवाद की सांस्कृतिक पैठ और भारतीय प्रतिक्रिया' पर अपने विचार प्रस्तुत

एसपीयू का छठा दीक्षांत समारोह आयोजित



अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 12 नवम्बर। सिक्किम के पेशेवर उच्च शिक्षण संस्थान सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एसपीयू) के बुदांग कैम्पस में 6वें दीक्षांत समारोह का आज आयोजन किया गया जिसमें 123 छात्रों ने विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त कीं। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा मुख्य अतिथि, शिक्षा सचिव डीसी नेपाल सम्माननीय अतिथि और जोरथांग विधायक श्रीमती सुनीता गजमेर विशिष्ट अतिथि के रूप में

विभिन्न विषयों के 123 छात्रों ने प्राप्त की डिग्रियां

सहयोग हेतु मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस कैम्पस की स्थापना से बुदांग और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
बुदांग परिसर का उद्घाटन 31 अक्टूबर, 2020 को हुआ था। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीबीए, एमबीए, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम., बीए, इको, एमए. इको, बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी, बीए और एमए पर्यटन, एमएससी भूगोल, बीएससी (ऑनर्स) कृषि, एमएससी कृषि विज्ञान, कृषि डिप्लोमा, बीएससी

सिक्किम सरकार व आईसीसीआर के समझौते से नई संभावनाएं : मंत्री लेप्चा

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 12 नवम्बर। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और सिक्किम सरकार के बीच कल नई दिल्ली के आजाद भवन स्थित आईसीसीआर में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिक्किम सरकार की ओर से राज्य के संस्कृति विभागीय सचिव कर्मा आर. बोन्पो और आईसीसीआर की ओर से अतिरिक्त सचिव व महानिदेशक कुमार तुहिन द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सिक्किम के संस्कृति मंत्री साम्पु लेप्चा और आईसीसीआर अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे उपस्थित रहे।
इस अवसर पर मंत्री लेप्चा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने सिक्किम की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सिक्किम के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है और आईसीसीआर के साथ यह साझेदारी उसे दुनिया के विभिन्न देशों को अपनी समृद्ध विरासत दिखाने में सक्षम बनाएगी। उनके अनुसार एक पर्यटन संचालित



अर्थव्यवस्था वाले राज्य के तौर पर सिक्किम के ब्रांड निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक बिरादरी के बीच अलग पहचान बनेगी।
वहीं आईसीसीआर अध्यक्ष ने यहां कहा कि संगठन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने हेतु राज्यों के साथ काम करने का इच्छुक है। साथ ही उन्होंने आईसीसीआर के साथ अपने राज्य के स्थापना दिवस समारोह के आयोजन हेतु सिक्किम का भी स्वागत किया।

NAGALAND STATE LOTTERIES

DEAR GOVERNMENT LOTTERIES

डियर 500 बय-मंथली लॉटरी

गारंटीड

प्रथम पुरस्कार

₹ 2.50 करोड़

(Seller ₹ 2 Lakhs + Sub Agent ₹ 50,000 Total Prize Amount ₹ 2.525 Crores)

प्रथम पुरस्कार केवल बिक्री की गयी टिकटों में से ही निकाला जायेगा

दूसरा पुरस्कार

₹ 1 करोड़

(₹ 10 Lakhs x 10 Prizes) (Seller ₹ 1 Lakh + Sub Agent ₹ 50,000 Total Prize Amount ₹ 1.15 Crores)

तीसरा पुरस्कार

₹ 1 करोड़

(₹ 5 Lakhs x 20 Prizes) (Seller ₹ 50,000 + Sub Agent ₹ 25,000 Total Prize Amount ₹ 1.15 Crores)

₹ 5 करोड़ के विजेता

<p>DEAR DIWALI KALI PUJA BUMPER</p> <p>Mr. SUMAN DASMAHANTA JHARGRAM, WEST BENGAL Draw Date: 25.10.2022 Ticket No. 35290</p>	<p>DEAR DIWALI SPECIAL BUMPER</p> <p>Mr. RUDRA PRATAP MAHANTY BANKURA, WEST BENGAL Draw Date: 22.10.2022 Ticket No. 8 824824</p>	<p>DEAR DURGA PUJA BUMPER</p> <p>Mr. SUDIP MAITY DELHI Draw Date: 08.10.2022 Ticket No. 44343</p>	<p>DEAR CHRISTMAS & NEW YEAR BUMPER</p> <p>Mr. ATTAR SINGH BHIWANI, HARYANA Draw Date: 01.01.2022 Ticket No. 76465</p>
<p>DEAR DIWALI KALI PUJA</p> <p>Mr. SUNIL BISWAS Ticket No. 15515 Draw Date: 04.11.2021</p>	<p>DEAR DURGA PUJA</p> <p>Mr. RIPAN SARKAR Ticket No. 90418 Draw Date: 15.10.2021</p>	<p>DEAR BAISAKHI</p> <p>Mr. RAJKANT PATIL Ticket No. 212083 Draw Date: 19.04.2021</p>	<p>DEAR MAHASHIVRATRI</p> <p>Mr. VIVEK KUMAR Ticket No. 409892 Draw Date: 12.05.2021</p>
<p>DEAR 2000</p> <p>Mr. RAJIV KUMAR Ticket No. 192943 Draw Date: 21.11.2020</p>	<p>DEAR DIWALI</p> <p>Mr. SK SABED HOSSAIN Ticket No. G 17947 Draw Date: 14.11.2020</p>	<p>DEAR 2000</p> <p>Mr. DEBENDRA AGARWALA Ticket No. 192432 Draw Date: 07.11.2020</p>	<p>DEAR MONTHLY</p> <p>Mr. GANESH PRASAD VARMA Ticket No. 38886 Draw Date: 03.03.2020</p>
<p>DEAR DIWALI</p> <p>Mr. SUJEN SARKAR Ticket No. L 14396 Draw Date: 02.11.2019</p>	<p>DEAR GOVERNMENT LOTTERIES</p> <p>₹ 5 Crores x 14, ₹ 3 Crores x 2, ₹ 2.50 Crores x 9, ₹ 2.10 Crores x 4, ₹ 2 Crores x 7, ₹ 1.50 Crores x 3, ₹ 1.25 Crores x 10 & ₹ 1 Crore x 1787 WINNERS (From 16.04.2019 to 06.11.2022)</p> <p>ने बनाए हैं 1836 करोड़पति</p> <p>क्या आप अगले करोड़पति हैं?</p> <p>FOR TICKETS & TRADE ENQUIRIES, CALL : SIKKIM 77193-66998</p> <p>टिकट सभी लॉटरी काउन्टरों पर उपलब्ध हैं</p>		

हिमाचल में बंपर वोटिंग, छिटपुट घटनाओं के बीच करीब 75 प्रतिशत हुआ मतदान



शिमला, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों के 412 प्रत्याशियों का भविष्य शनिवार को ईवीएम में कैद हो गया है। राज्य में लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आहुति डालने के लिए मतदाता सुबह ही मतदान केंद्रों में पहुंच गए। छिटपुट घटनाओं के बीच इस चुनाव में बंपर वोटिंग देखने को मिली और मतदान करीब 74.61 प्रतिशत पहुंच गया, हालांकि पिछले चुनाव से कम रहा। अभी बैलेट पेपर से किए गए मतदान की गिनती होनी है। इसलिए मत प्रतिशतता 75 फीसदी से ज्यादा पहुंचेगी। कई बूथों पर पांच बजे

के बाद भी मतदान होता रहा। सोलन में 86, कुल्लू में 40, मंडी में 35, ऊना में 26 और हमीरपुर में पांच बूथों पर देर तक मतदान होता रहा। हालांकि कुछ जगह ईवीएम की खराबी और अन्य कारणों के चलते देर रात तक मतदान चलता रहा। नालागढ़ के डरोली में रात 10:37 बजे तक मतदान हुआ। इसलिए मत प्रतिशतता बढ़ने की संभावना है। सबसे अधिक मतदान दून विधानसभा क्षेत्र में 85.20 प्रतिशत हुआ, जबकि कसुम्पटी में सबसे कम 57 प्रतिशत रहा। मतदान करने में सिरमौर जिला अन्वल रहा, जहां 78.00 प्रतिशत मतदान हुआ है और

सबसे कम वोट हमीरपुर जिले में 71.18 प्रतिशत पड़े। राज्य के 7,881 मतदान केंद्रों में सुबह 8 बजे से देर शाम तक वोटिंग होती रही। मतदान के बीच राज्य में मौसम साफ रहा, जबकि बर्फ वाले क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे रहा। इन क्षेत्रों में शून्य से नीचे तापमान होने पर भी मतदाता वोट डालने पहुंचे। प्रदेश में कई स्थानों पर ईवीएम के खराब होने की भी सूचना रही, जिससे चुनाव कुछ समय के लिए बाधित रहा। चुनावी दंगल में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), माकपा, बसपा और निर्दलियों समेत

सीए लागू करने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध : सीएम सरमा

दिसपुर, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीए) को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरमा ने कहा कि समय आने पर इसके लिए नियम बनाए जाएंगे।



एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, अपनी मातृभूमि में नागरिक बनना एक हिंदू का वैध अधिकार है और भाजपा पूरी तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ खड़ी है। उसने जब सवाल किया गया कि अधिनियम के नियम अभी तक क्यों नहीं बनाए गए, सरमा ने कहा कि सीए का विरोध करने वाले लोग थे और उसके बाद कोरोना वायरस महामारी आ गई। उन्होंने आगे कहा, यह प्रक्रिया में है, लेकिन भाजपा इसके लिए प्रतिबद्ध है। संसद ने कानून पारित किया है, यह समय की बात की बात है, जब आप इसके लिए नियम देखेंगे। मुख्यमंत्री सरमा ने इन आरोपों को भी खारिज किया कि भगवा पार्टी सीए को चुनाव के

लिए इस्तेमाल करती है। जो लोग सीए के कारण वोट करेंगे, वो देश के परिदृश्य में दो से तीन संसदीय सीटों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा, सीए हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह हमारी विचारधारा का हिस्सा है। हम इसे लागू करेंगे। किसी ने सवाल किया कि राम मंदिर कहां, कब आएगा? आपने अभी राम मंदिर देखा है। किसी ने सवाल किया कि अनुच्छेद 370 कब हट जाएगा? यह हट गया है। जिस तरह आप समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को आते हुए देखेंगे, उसी तरह आप सीए को आते हुए देखेंगे।

सीए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिमों (हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों) को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया था। इसके अगले दिन इसे राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई। बाद में गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। हालांकि, इस कानून को लागू किया जाना बाकी है, क्योंकि सीए के तहत नियम अभी बनाए जाने बाकी हैं। इसको लागू करने के लिए कानून के तहत नियम बनाए जाएंगे।

2000 से ज्यादा बच्चों को मिलेंगे लैपटॉप, योगी सरकार ने जारी की धनराशि



लखनऊ, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। यूपी के दो हजार से ज्यादा बच्चों के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। इन बच्चों को योगी सरकार लैपटॉप देगी। इसके लिए योगी सरकार ने धनराशि जारी कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड महामारी के दौरान अपने माता-पिता (या अभिभावकों) को खोने वाले 13,371 बच्चों के लिए पहली छमाही किस्त जारी की है। इस योजना के तहत निराश्रित बच्चों को उनके भरण-पोषण के लिए प्रति माह 4,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। सरकारी आदेश के अनुसार राज्य ने पहले शैक्षणिक वर्ष 2022-

23 के लिए दो त्रैमासिक किस्तें- प्रति बच्चा 2,500 रुपये प्रति माह- जारी की थीं। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे- जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च, 2020 के बाद- कोविड-19 के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो, को भी योजना के तहत धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, 2,217 छात्रों को लैपटॉप प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को धनराशि भी जारी की गई है। इसके अलावा, राज्य ने पांच महिलाओं के लिए विवाह अनुदान भी जारी किया है। 18 से 23 वर्ष की आयु के किशोर जो कोविड या अन्य कारणों से अपने

माता-पिता या अभिभावक को खो चुके हैं और उच्च शिक्षा (बारहवीं कक्षा पूरी करने के बाद) कर रहे हैं, उन्हें भी वित्तीय सहायता दी जाती है। इस बीच, तलाकशुदा (या परित्यक्त) माताओं वाले बच्चों और बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति या बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त हुए बच्चों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी तरह, यदि किसी परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य कारावास में है, तो राज्य उनके बच्चों को भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को दिया जाता है।

जलबोर्ड में हुए 20 करोड़ के घोटाले में एसीबी ने दर्ज की एफआईआर, प्राइवेट कंपनी और बैंक रडार पर

नई दिल्ली, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। दिल्ली जलबोर्ड में 20 करोड़ के घोटाले के मामले में शनिवार को एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा) ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारियों ने निजी कंपनी व एक बैंक के साथ मिलकर 20 करोड़ से अधिक रकम की गड़बड़ी की है। मामला संज्ञान में आने के बाद सितंबर माह में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस संबंध में मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। मामले में गड़बड़ी की रकम को भी वापस हासिल करने के लिए कहा गया था। उपराज्यपाल के आदेश के बाद मामले की जांच करवाने पर आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसीबी को मामला दर्ज

करने के लिए कहा गया। एसीबी ने भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अलावा धोखाधड़ी, अमानत में ख्यात और आपराधिक षडयंत्र का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार गड़बड़ी के मामले में पाया गया कि जलबोर्ड ग्राहकों से लिए बिल जलबोर्ड के खाते में भेजने के बजाए एक निजी बैंक के खाते में भेजा गया। जो नियमों का उल्लंघन था। दरअसल जून 2012 में दिल्ली जलबोर्ड ने कॉर्पोरेशन बैंक को तीन साल के लिए पानी का बिल एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद इसे 2016 और 2017 में जारी रखने के लिए कहा गया। इस दौरान 2019 में गड़बड़ी का खुलासा हुआ तो तब भी उनके पास यह अधिकार जारी रखा गया। आरोप है कि बैंक ने दिल्ली

जलबोर्ड के अधिकारियों से मिली भगत कर तय नियमों को ताक में रखकर एक निजी कंपनी को बिल एकत्रित करने व उसे जलबोर्ड के खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी दे दी। यह सब उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जलबोर्ड के अध्यक्ष थे। 11 जुलाई 2012 से 10 अक्टूबर 2019 के बीच रुपये जमा कराने में 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की गड़बड़ी हुई थी। यह रकम ग्राहकों से तो ले ली गई, लेकिन जलबोर्ड के बैंक खाते में जमा नहीं हुई। इसके बाद भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने बैंक के अनुबंध को वर्ष 2020 तक के लिए बढ़ा दिया। इस गड़बड़ी में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह प्रत्येक बिल के कमीशन को पांच रुपये से बढ़ाकर छह रुपये कर दिया गया।

नियम के तहत बिल के रूप में वसूली गई रकम को 24 घंटे के भीतर जमा करना होता था। इस नियम में भी कंपनी को ढील दे दी गई। खानबीन के दौरान पता चला कि रकम फेडरल बैंक के एक खाते में जमा हो रही थी। वहां से रकम जलबोर्ड के खाते की जगह एक निजी कंपनी के खाते में जमा हो रही थी। किसी अन्य बैंक के खाते में रकम का जमा होना नियमों का उल्लंघन था। कॉर्पोरेशन बैंक ने इस काम को किया और जलबोर्ड अधिकारियों ने गड़बड़ी पर चुप्पी साधे रखी। इन सब का पता चलने पर एलजी ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। एसीबी अब मामला दर्ज कर गड़बड़ी का पता लगाने का प्रयास करेगी।

एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली-एनसीआर में लगे भूकंप के तेज झटके

राजेश अलख नई दिल्ली, 12 नवम्बर। दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में शनिवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका 5.4 तीव्रता का था और इसका केंद्र नेपाल में था जो उत्तराखंड में जोशमठ से 212 किलोमीटर दूर है। भूकंप का झटका शाम सात बजकर 57 मिनट पर महसूस किया गया। लोग ऑफिस

और घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। यह झटके 7 बजकर 58 मिनट पर लगे। लोग सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार, भूकंप के झटके 50 सेकेंड तक लगे। इससे पहले बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बुधवार आधिरात को दो बार दिल्ली-एनसीआर की धरती हिली थी। इसके बाद लोग दहशत में आ गए थे।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में था। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, मुनस्यारी और गंगोलीहाट सहित कई स्थानों पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। पिथौरागढ़ के आपदा प्रबंधन अधिकारी बीएस महर ने बताया,

भूकंप की उत्पत्ति 10 किलोमीटर सतह के नीचे हुई थी और यह स्थान नेपाल के सिलंगा शहर से तीन किलोमीटर दूर था। प्रभावित देश भारत, चीन और नेपाल हैं। भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान की जानकारी फौरन नहीं मिल सकी। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

केवल पैसा बनाने में लगी है हेमंत सरकार : बाबूलाल मरांडी



गिरिडीह, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। झारखंड में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। शनिवार को राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का आदिवासियों के कल्याण से कोई लेना-देना नहीं है और वह केवल पैसा बनाने के इरादे से काम कर रही है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने ये आरोप गिरिडीह जिले के तिसरी ब्लॉक में एक रैली के दौरान लगाए। इस दौरान उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़े किए। रैली का नेतृत्व करते हुए राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। राज्य में विकास कार्य ठप हैं, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का गरीबों और आदिवासियों से कोई नाता नहीं रह गया है। सरकार का पूरा ध्यान केवल रुपये कमाने में

लगा हुआ है। पूर्व सीएम मरांडी ने आरोप लगाया कि सोरेन सरकार में हत्या, बलात्कार और लूट के मामले कई गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग रेत की कमी का सामना कर रहे हैं लेकिन सरकार पिछले तीन साल में एक भी रेत घाट की नीलामी नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार से कहा था कि अगर वह नीलामी नहीं कर सकती है तो वह राज्य के लोगों के लिए बालू घाटों को मुफ्त कर दें। लेकिन, वह ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने तस्करी कर रेत ले जाने वाले ट्रेक्टरों से पैसा बनाने के लिए पुलिस को लगाया है। पूर्व सीएम का यह बयान तब आया है जब एक दिन पहले यानी 11 नवंबर को सोरेन सरकार ने राज्य विधानसभा में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने के लिए और 1932 भूमि रिकॉर्ड से संबंधित विधेयक को पारित किया है। सरकार इस विधेयक के जरिए आदिवासियों के बीच अपने समर्थन आधार को मजबूत करने के प्रयास में है।



मोरबी हादसे के बाद एक्शन में योगी सरकार, यूपी के छह पुलों की मरम्मत के आदेश

लखनऊ, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। गुजरात के मोरबी में ब्रिज टूटने से हुए हादसे के बाद प्रदेश में कराए गए पुलों के सर्वे में छह पुल खतरनाक स्थिति में पाए गए हैं। इन पुलों की मरम्मत का आदेश दिया गया है। चार पुलों की मरम्मत के लिए बजट जारी कर दिया गया है। खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके दो अन्य पुलों की मरम्मत के लिए बजट का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। मोरबी की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्थित समस्त पुलों की सुरक्षा जांच करते हुए रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। लोक निर्माण

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस खूबे में राज्य में 25 पुल मरम्मत के योग्य पाए गए हैं। इनमें से छह ऐसे हैं जिनकी मरम्मत तत्काल कराया जाना आवश्यक है। अन्य पुलों की मरम्मत का काम किया जाना जरूरी है लेकिन तात्कालिक तौर पर वे खतरनाक स्थिति में नहीं हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण ने बताया है कि तत्काल मरम्मत की श्रेणी में चिन्हित किए गए छह में से चार पुलों की मरम्मत का बजट जारी कर दिया गया है। शेष दो पुलों की मरम्मत के लिए बजट जल्द जारी हो जाएगा। इसकी फाइल तैयार कर



वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है। अन्य 19 पुलों की मरम्मत कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। इस सर्वे में सेंटु निगम ने कुल 5283 पुलों (सेतुओं) की जांच की। जिसमें 4945 पक्के पुल, 294 निर्माणधीन पक्के पुल और 44 पांढर पुल शामिल हैं। इनमें से जो 25 पुल असुरक्षित पाए गए हैं वह मेरठ, चंदौली, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, आगरा, वाराणसी, जौनपुर, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद जिले में हैं। बरेली जिले के परसापुर में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत के लिए 4.88 करोड़ तथा मुरादाबाद-फरूखाबाद मार्ग पर स्थित पुल की मरम्मत के लिए 1.01 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। 140 लाख रुपये तक के प्रस्ताव विभाग मुख्यालय स्तर से जारी किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता (सेतु) अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया है कि तत्काल मरम्मत वाले छह पुलों पर भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। इन छह के अलावा प्रेष 19 पुलों की मरम्मत का प्रस्ताव भी क्षेत्र से मांगा गया है। प्रस्ताव आने के साथ ही सभी पुलों की मरम्मत के लिए बजट जारी किया जाएगा।

मुश्किल, सही फैसला

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सभी छह अपराधियों को जेल से रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हर लिहाज से एक बड़ा फैसला है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का यह मामला हर देशवासी की संवेदना से जुड़ा है। ऐसे में स्वाभाविक ही इसके पक्ष-विपक्ष में तीव्र भावनाएं भी पूरे देश में हैं।

लेकिन न्याय से जुड़े किसी मामले को सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं देखा जा सकता। न ही सजा का उद्देश्य अपराधी का उत्पीड़न होता है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से देश की न्याय व्यवस्था की परिपक्वता का संदेश गया है। इसमें दो राय नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या एक ऐसी घटना है, जिसे यह देश कभी भूल नहीं सकता। लेकिन जहां तक इस घटना को अंजाम देने वालों का सवाल है तो देश की न्यायपालिका ने उनके कृत्य के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपयुक्त सजा सुनाई।

अपराधियों के लिए बने कानूनों के प्रावधानों के तहत ही बाद में यह बात उठी कि वे सब अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जेल में बिता चुके हैं। उनमें से कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उन सबका जेल में आचरण अच्छा पाया गया है। कई ने जेल में रहते हुए गंभीर अध्ययन किया और उनके काम की बाहर भी तारीफ हुई। इन्हीं आधारों पर तमिलनाडु सरकार ने इन कैदियों की दया याचिका पर पॉजिटिव फैसला करते हुए इन्हें जेल से रिहा करने की सिफारिश की। मगर 2018 में की गई इस सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में एक कैदी के मामले पर सुनवाई करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया और अब उसी केस को आधार बनाते हुए बाकी सबको भी मुक्त करने का फैसला दिया। निश्चित रूप से इस फैसले का राजनीतिक पक्ष भी है।

तमिलनाडु ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इस पर पक्ष-विपक्ष में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली प्रतिक्रिया इस फैसले को गलत और अस्वीकार्य बताया है। लेकिन जहां तक गांधी परिवार की बात है तो प्रियंका गांधी ने जेल में नलिनी से मुलाकात की थी। बाद में उनका बयान आया कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है। राहुल गांधी भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनके मन में इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं है। पिता, पति या ऐसे ही अपने किसी करीबी को खोने का दुख तो आजीवन संग रहता है, लेकिन इसके बावजूद अगर यह परिवार इससे ऊपर उठकर उन लोगों को माफ कर सका है तो यह बड़ी बात है। समाज, देश और पार्टियों को भी निजी दुखों और भावनाओं से ऊपर उठकर न्याय की उदात्त दृष्टि को समझने और अपनाने की जरूरत है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

फिर से पीली क्रांति की दरकार

योगेश साहू
अनुवंशिक रूप से परिष्कृत (जीएम) सरसों की किस्म को पर्यावरणीय मंजूरी मिलना वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जश्न का अवसर हो सकता है। आखिर यह पहला जीएम खाद्य है, जिसे पर्यावरण परीक्षण की मंजूरी मिली है। कहा गया है कि इससे खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भले ही ये दावे सच न हों, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का एक प्रमुख वर्ग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग निश्चित रूप से जानता है कि यह कम से कम देश में अन्य जीएम खाद्य पदार्थों के लिए दरवाजा खोल देगा।

तथ्य यह है कि भारत 1.15 लाख करोड़ रुपये की लागत से खाद्य तेल की अपनी मांग का 55 से 60 प्रतिशत आयात करता है, जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। तत्काल आवश्यकता आयात को कम करने की है और यह तभी हो सकता है जब घरेलू उत्पादन बढ़े। यह देखते हुए, कि देश में नौ खाद्य तेल फसलें उगाई जाती हैं, इस भारी कमी को पूरा करने के लिए हमें इन सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि कम उपज वाली जीएम सरसों की किस्म सरसों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकती है?

जीएम फसलों से जुड़े सभी मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों को देखते हुए और यह जानते हुए कि जीएम सरसों किस्म की उत्पादकता कम है, इसे वैज्ञानिक कूड़ेदान तक ही सीमित रखा जाना चाहिए था। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चाहे कितना भी जोर दें, ये दावे वास्तव में निराधार और वैज्ञानिक रूप से अमान्य हैं। यह सच है कि देश में सरसों की औसत उत्पादकता 2,000

किलोग्राम/हेक्टेयर के वैश्विक औसत के मुकाबले 1,260 किलोग्राम/हेक्टेयर है, और निश्चित रूप से घरेलू उत्पादकता के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है।

पर शायद जीएम सरसों को पर्यावरणीय मंजूरी देने वाला मंत्रालय यह भूल गया है कि प्रो. एमएस स्वामीनाथन ने क्या कहा था। जीएम का विकल्प सबसे अंत में आजमाना चाहिए, जब अन्य सभी उपलब्ध विकल्प खत्म हो जाएं। जीएम सरसों की किस्म-डीएमएच 11 से खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना, जिसकी उत्पादकता सरसों की कम-से-कम पांच उपलब्ध किस्मों की तुलना में कम है, एक वैज्ञानिक चमत्कार ही होगा।

जीएम सरसों की उत्पादकता की तुलना अपेक्षाकृत खराब उपज देने वाली वरुणा किस्म से करके यह दावा करना कि यह 28 फीसदी अधिक उपज है, वास्तव में जीएम किस्म की कम उपज को छिपाने का चतुर तरीका है। किसानों के पास पहले से उपलब्ध पांच उच्च उपज देने वाली किस्मों में से (जो सभी गैर-जीएम किस्में हैं) तीन उसी डीएमएच शृंखला से हैं। आनुवंशिक रूप से परिष्कृत डीएमएच-11 किस्म की 2,626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उपज क्षमता के मुकाबले, पहले से उपलब्ध डीएमएच-4 किस्म की उपज क्षमता 3,012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जिसका अर्थ है कि यह जीएम सरसों किस्म की तुलना में 14.7 प्रतिशत अधिक उपज देती है।

जीएम सरसों किस्म की उत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए सरसों की इस किस्म का उपयोग क्यों नहीं किया गया, यह स्पष्ट है। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि जीएम सरसों कम से कम वैज्ञानिकों की और अधिक संकर

किस्म पैदा करने के लिए एक उपकरण उपलब्ध कराएगी। हालांकि तथ्य यह है कि डीएमएच शृंखला का अर्थ है-धारा सरसों का संकर किस्म, और हमारे पास पहले से ही गैर-जीएम प्रौद्योगिकी के साथ उच्च उपज वाले संकर किस्म हैं।

हमें यह आभास देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि पारंपरिक किस्मों के साथ सरसों के संकर किस्म का उत्पादन नहीं किया गया है। भारत में सरसों की खेती 80 से 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। हैरानी की बात यह है कि बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में पैदावार पहले से ही अधिक है, जहां सरसों की गहन खेती प्रणाली का पालन किया गया। बिहार में सरसों की औसत उपज 3,458 किलोग्राम/हेक्टेयर है और राजस्थान में उससे थोड़ा ज्यादा 3,560 किलोग्राम/हेक्टेयर है, जो स्वीकृत जीएम सरसों की किस्म से काफी अधिक है।

मध्य प्रदेश में, कृषि विभाग द्वारा एसएमआई उत्पादन प्रणाली लागू करने के बाद प्राप्त औसत पैदावार 4,693 किलोग्राम/हेक्टेयर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आश्चर्य है कि कृषि वैज्ञानिक एसएमआई खेती के तहत सरसों की खेती को बढ़ावा और विस्तार देने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, खासकर यह देखते हुए कि मध्य प्रदेश में उपज जीएम किस्म की तुलना में लगभग दोगुनी है। एक ऐसे देश में, जहां सरसों के लिए एक विशाल आनुवंशिक विविधता मौजूद है, भारत को इसके बजाय भूली हुई पीली क्रांति से ऊपर उठने की जरूरत है।

वर्ष 1985-86 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आयात पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की

हैं, उससे भी भारत मैन्यूफैक्चरिंग के एक बेहतर हब के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहा है। मोदी के अनुसार, इस समय भारत का उद्योग-कारोबार सेक्टर करीब 160 से अधिक देशों की कंपनियों के निवेश से सुसज्जित है।

भारत में विदेशी निवेश कुछ उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के 61 क्षेत्रों में फैले हुए हैं और भारत के 31 राज्यों को कवर करते हैं। उल्लेखनीय है कि इस समय दुनिया भर में मेक इन इंडिया की मांग बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में मैन्यूफैक्चरिंग के तहत 24 सेक्टर को प्राथमिकता के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चीन से आयात किए जाने वाले दवाइ, रसायन और अन्य कच्चे माल का विकल्प तैयार करने के लिए पिछले दो वर्ष में सरकार ने प्रोडक्शन लिंकड इनसैटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब दो लाख करोड़ रुपये आवंटन के साथ प्रोत्साहन सुनिश्चित किए हैं। अब देश के कुछ उत्पादक चीन के कच्चे माल का विकल्प बनाने

में सफल भी हुए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पीएलआई स्कीम की सफलता के कारण ही वर्ष 2022-23 में अप्रैल-अगस्त के दौरान फार्मा उत्पादों के आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40 फीसदी की कमी आई है और निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 3.47 फीसदी की वृद्धि हुई है।

निश्चित रूप से जिस तरह भारत की नई लॉजिस्टिक नीति 2022 और गति शक्ति योजना का आगाज अभूतपूर्व रणनीतियों के साथ हुआ है, उससे भी भारत आर्थिक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में तेजी से आगे बढ़ेगा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में एक नवंबर को डिजिटल रुपये की शुरुआत और नौ नवंबर को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निर्यातकों को निर्यात लाभों का दावा रुपये में करने में सक्षम बनाए जाने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय से भी देश को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाए जाने में मदद मिलेगी।

सस्ती लागत ने बढ़ाई संभावनाएं

जयंतीलाल भंडारी

इस समय भारत मेक इन इंडिया ही नहीं, वन मेक फॉर द ग्लोबल के मंत्र के साथ मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की जिस राह पर आगे बढ़ रहा है, उसकी चमक वैश्विक व्यापार के 75 फीसदी से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले जी-20 की बैठक में नजर आ सकती है, अगले साल जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के कोने-कोने में जी-20 के करीब 200 विभिन्न कार्य समूह की बैठकों के दौरान दुनिया नए सामर्थ्यवान भारत और उभरते हुए मैन्यूफैक्चरिंग हब को नजदीक से देख पाएगी।

निस्सर्देह भारत के मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की अनुकूलताएं एक के बाद एक उभरकर दिखाई दे रही हैं। हाल ही में तीन नवंबर को प्रकाशित 85 देशों के मैन्यूफैक्चरिंग से संबंधित विभिन्न कारकों का समग्र मूल्यांकन करने वाली विश्व प्रसिद्ध यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट-2022 के तहत सस्ते विनिर्माण के मद्देनजर भारत की 100 प्रतिशत अंक दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने चीन और वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर में सबसे कम विनिर्माण लागत वाले देश का दर्जा हासिल कर लिया है। हालांकि इस रिपोर्ट में अनुकूल कर वातावरण और 'पारदर्शी सरकारी नीतियां' जैसी श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन अब भी सुधार योग्य कहा गया है। भारत के मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने के परिप्रेक्ष्य में अधिक विनिर्माण लागत सबसे बड़ी चुनौती रही है, ऐसे में जहां अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में मैन्यूफैक्चरिंग लागत में कमी भारत के लिए सुकूनदेह है, वहीं देश में तेजी से आर्थिक सुधारों ने भी उसकी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है।

विगत तीन नवंबर को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र में देश के सबसे पहले सी-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास करते हुए कहा कि पिछले आठ वर्षों में सरकार ने जिस तरह कई आर्थिक सुधारों को अपनाया है और कई प्रोत्साहन दिए

न पैसा और न इंतजाम कैसे थमेगा प्रदूषण

दत्ता सामंत

बोलने के लिए पिछले तीन दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं और मेरी बारी अब आई है। ...प्रदूषण एक ऐसा विषय है, जिसकी किसी को भी चिंता नहीं है, हालांकि, प्रदूषण रोकने के लिए कई विधेयक पारित किए जा चुके हैं। मेरे विचार से इस बारे में एक केंद्रीय कानून भी है। कुछ राज्य कानून भी हैं। इसके अलावा प्रदूषण निवारण के लिए एक बोर्ड भी है। ये सभी चीजें हैं, किन्तु अब आप कहते हैं कि ये काम नहीं कर रही हैं। इसीलिए आप इस सूची में एक और कानून शामिल कर रहे हैं।

हालांकि, इतने अधिनियम हैं, किन्तु धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ...हम कितनी ही चर्चाएं करते हैं, किन्तु मेरा विचार है कि अधिनियम में निहित उपबन्धों का एक छोट सा अंश भी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

मेरे पास सही-सही आंकड़े हैं और मैं उन्हें उद्धृत करूंगा। वातावरण में प्रदूषण की मात्रा मापने के लिए आपके पास कितनी प्रयोगशालाएं हैं? मेरे विचार से 30 या 40 सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से अधिक नहीं हैं। क्या आप इतनी कम प्रयोगशालाओं से काम चला

सकते हैं? गैर-सकारी प्रयोगशालाओं की स्थिति क्या है, आपके इन सब बातों की ओर ध्यान देना होगा। दूसरे, क्या आप सभी उद्योगों को शामिल करने जा रहे हैं? ...इसके पश्चात मोटर वाहनों को लीजिए, जो अधिकतम प्रदूषण फैलाते हैं, जहां तक वायु प्रदूषण का संबंध है। महाराष्ट्र में ही लगभग 20 लाख वाहन हैं। अकेले बम्बई शहर में करीब 10 लाख वाहन हैं। दिल्ली में ही शहर की सड़कों पर 10.05 लाख वाहन चलते हैं। इन वाहनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को मापने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था

है? क्या ऐसे कार्य के लिए आपके पास कोई तंत्र है? ऐसी चीजों पर कार्रवाई के बजाय हम अनावश्यक बहस कर सदन का वक्त बर्बाद कर रहे हैं।

अब मैं कुछ उन महत्वपूर्ण उद्योगों पर आता हूं, जो देश में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि कर रहे हैं। देश में इस समय कागज की लुगदी के लगभग 179 यूनिट हैं।... देश में करीब 10 लाख वाहन हैं। दिल्ली में ही शहर की सड़कों पर 10.05 लाख वाहन चलते हैं। इन वाहनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को मापने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था

यह जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है

पवन के. वर्मा

पाकिस्तान में किसी शीर्ष राजनेता की हत्या का प्रयास करने वाले अमूमन अपना निशाना चूकते नहीं हैं। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान 1951 में गोलियों से मार दिए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जिया-उल-हक ने एक कंगारू-कोर्ट के जरिए मारा ही था।

उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो भी 2007 में मारी गई। विगत 3 नवम्बर को वजीराबाद में इमरान खान पर गोलियां चलाई गईं, जब वे इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे। उन्हें पैर में चार गोलियां लगीं, लेकिन उनकी जान बच गई। यह चमत्कार कैसे हुआ?

इस प्रश्न के तीन उत्तर हैं। एक, पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के प्रति उभरता असंतोष, दो, पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और तीन, इमरान खान की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता। अभी तक तो यही स्थिति थी कि पाकिस्तान की फौज निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को आसानी से किनारे कर देती थी। नागरिक सरकारें फौज की इजाजत से गठित की जातीं।

फौज की नाराजी के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता। आज तक किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इमरान भी 2018 में फौज की पसंद से ही सत्ता में आए थे। लेकिन इसके बाद उनका प्रभाव बढ़ता चला गया।

वे अपनी स्वतंत्र विदेश-नीति चलाने लगे और फौज के मामलों में भी दखल देने लगे। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा का विरोध किया और उनके खिलाफ आईएसआई प्रमुख फैजल हमीद का समर्थन किया। अप्रैल 2022 में इमरान को फौज की कथित सहमति से अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हट दिया गया।

फौज को लगता था इसके बाद इमरान दृश्य से ओझल हो जाएंगे। या उन पर इतने कानूनी मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे कि वे खुद ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन इमरान ने ऐतिहासिक रूप से फौज का मुकाबला करने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों से सीधे संवाद किया और हकीकी आजादी यानी वास्तविक लोकतंत्र की गुहार लगाई। उन्होंने फौज पर अलोकतांत्रिक, गैरजिम्मेदार और भ्रष्ट होने के आरोप लगाए।

उनके अभियान से प्रेरित होकर अवाम नारे लगाने लगी कि यह जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। इमरान को पद से बेदखल करने के तीन महीने बाद उनकी पार्टी ने जुलाई 2022 में पंजाब के उपचुनावों में बड़ी सफलता दर्ज की और 20 में से 15 सीटें जीत लीं। जबकि पंजाब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) का गढ़ माना जाता है। इस्लामाबाद के लिए उनका लॉन्ग मार्च लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। इमरान पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं।

यहां विडम्बना यह है कि इमरान खुद लोकतांत्रिक नहीं हैं। वे फौज के समर्थन से सत्ता में आए और जब वे सरकार में थे तो फौज और आईएसआई की आलोचना करने वाले पत्रकारों पर हमले और उनके अपहरण होते रहते थे। लेकिन आज उनकी बदलाव की मुहिम को लोगों का समर्थन मिल रहा है तो इसका कारण है बदहाल इकोनॉमी।

पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था आईसीयू में जा चुकी है। इस साल आई भयानक बाढ़ ने उसका खासा नुकसान किया। महंगाई बेकाबू हो चुकी है, ईंधन की कीमतें आसमान में हैं, पाकिस्तानी रुपया धराशायी हो गया है और ऊर्जा-संकट मुंह बाए खड़ा है।

पाकिस्तान में आर्मी-आईएसआई कॉम्बो इमरान को मैसेज देना चाहता था कि वे अपनी मुहिम से पीछे हट जाएं। लेकिन साथ ही, वे अवाम के विरोध के डर से उन पर जानलेवा प्रहार भी नहीं कर सकते थे।

पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है और आईएमएफ के 7.2 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के आसरे हैं। पाकिस्तान की 64 प्रतिशत आबादी 30 वर्ष से कम उम्र वालों की है और ये नौजवान एक बेहतर भविष्य चाहते हैं। उन्हें इमरान में उम्मीद नजर आती है।

इनके चलते आर्मी और आईएसआई बैकफुट पर आ गए हैं। हो सकता है, अतीत की तरह वे पाकिस्तान पर सैन्य-शासन थोप दें लेकिन इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। शायद इस बार पाकिस्तान के लोग इसकी कड़ी मुखालफत करें और फौज की जड़ें हिल जाएं।

इसी कारण हमलावर निशाना चूक गया। आर्मी-आईएसआई कॉम्बो इमरान को मैसेज देना चाहता था कि वे पीछे हट जाएं। लेकिन साथ ही, वे लोगों के विरोध के डर से उन पर जानलेवा प्रहार भी नहीं कर सकते थे। यह एक सोची-समझी रणनीति थी, जो लगता नहीं कि बहुत कारगर साबित हुई है। इमरान ने अपना लॉन्ग मार्च फिर शुरू कर दिया है। उनका हीसला डिगा नहीं है। अगर पाकिस्तान में समय से पूर्व चुनाव होते हैं तो बहुत मुमकिन है कि इमरान सत्ता में शानदार वापसी करें।

की सही-सही संख्या का पता नहीं है, किन्तु इनमें से कोई भी तय उपबन्धों का पालन नहीं कर रहा है। कुल 70 उर्वरक यूनिट है, जिनमें से केवल 19 यूनिट ही सार्वधिक मानकों का पालन कर रहे हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में 729 क्रीटनाशक निर्माण यूनिट हैं और इनमें से कोई यूनिट सार्वधिक उपबन्धों का पालन नहीं कर रहा है। 104 सीमेंट यूनिटों में से केवल 15 ही मानकों का पालन कर रहे हैं। यदि दो या तीन प्रतिशत बड़े उद्योगों को भी प्रदूषण रोकने की परवाह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं?... स्वतंत्रता के 40 वर्ष बाद भी भारतवासी गन्दा पानी पी रहे हैं। जब तक आप इस बारे में कुछ करते नहीं, कुछ भी नहीं होगा।

मैंने जर्मनी और जापान में प्रदूषण की समस्याओं का अध्ययन किया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इन देशों का दौरा करें। ... आप अन्य बड़े उद्योगों को भी इस प्रकार हिदायतें क्यों नहीं देते कि वह ऐसी व्यवस्था करें, जिनसे प्रदूषण से बचा जा सके? मैं जर्मन लोगों की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा है कि वह यह सब पिछले 50 वर्षों से करते चले आ

रहे हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे इस सुझाव को संयुक्त चयन समिति को भेज दें। अन्यथा खाली बहस से प्रदूषण को इन सभी समस्याओं पर काबू पाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो नियोक्ता इस कानून का प्रयोग लोगों का शोषण करने के लिए करेंगे। ...में इसका सख्त विरोध करता हूं।... समूचे विधेयक में एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया गया है। ...देश में 8,50,000 उद्योग हैं। ... सिर्फ दिल्ली में ही 10,50,000 वाहन वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। आपकी क्या मशीनरी है? आप सैद्धांतिक स्तर पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

...यह एक सैद्धांतिक चर्चा है, जिसे सरकार बगैर कुछ ठोस किए कर रही है। आप जल प्रदूषण को रोक नहीं सकते। ...आपके पास कोई भी मशीनरी नहीं है। ...में एक डाक्टर हूं और मुझे प्रदूषण से होने वाले खतरों और कठिनाइयों का अच्छी तरह पता है। लोग धूल में काम करते हैं। ... जब आप इसे लागू ही नहीं करते हैं, तो इस अधिनियम का क्या उपयोग है?



बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं आउटडोर खेल

घर के बाहर जाकर खेलने के काफी फायदे हैं। तुम अपने दोस्तों के और करीब आते हो, टीमवर्क समझ आता है और तुम खूब बढ़ते हो। आउटडोर खेल ऐसे नहीं होते जिन्हें सदी-सदी के हिसाब से खेला जाए। तुम किसी भी खेल को कभी भी खेल सकते हो। बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट के अलावा कई पारंपरिक खेल भी खेल सकते हो।

ट्रेजर आइलैंड

डोरेमोन में तुमने इसका नाम सुना होगा। वहां जाकर नोबिता और उसके दोस्त मस्ती करते हैं। लेकिन हम जिस ट्रेजर आइलैंड की बात कर रहे हैं, उसे अलग-अलग जगहों पर कई तरह के नामों से जाना जाता है। इस गेम में दो टीम बनाती होती हैं। इसमें पहली टीम किसी भी चीज को खोजना बना कर छुपा देती है। फिर पहली टीम, दूसरी टीम के लिए वस्तु बनाती है। उन वस्तुओं को ढूँढते हुए उस खजाने तक पहुंचना होता है। इसमें तुम टाइमिंग भी शामिल कर सकते हो। जो भी टीम खजाने को ढूँढने में सफल हो जाती है, वह जीती हुई मानी जाती है।

छुपन-छुपाई

यह खेल सबसे पुराना है। तुम्हारे मम्मी-पापा ने भी इसे बचपन में जरूर खेला होगा। इसमें खूब सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं। एक बच्चे को डेन चुना जाता है। डेन चुनने के लिए तुम अक्कड़-बक्कड़ का सहारा ले सकते हो। फिर बाकी बचे सभी बच्चे अलग-अलग जगहों पर छुप जाते हैं और डेन उन्हें ढूँढता है। जिस बच्चे को वह सबसे पहले ढूँढ लेता है, अगली बार उसे ही डेन बनाना होता है। लेकिन एक को ढूँढने से ही काम नहीं चलता। उसे सभी को ढूँढना होता है।



बनी कैसे ऊन?

दोस्तों, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिस ऊन का स्वेटर पहन हम सर्दी से बचते हैं, वह बनी कैसे? जरूर वो इंसान बहुत ही बुद्धिमान होगा, जिसने भेड़ को देखकर उससे ऊन बनाने के प्रयोग करने के बारे में सोचा होगा। यह माना जाता है कि बुनने के लिए ऊन का ही सर्वप्रथम उपयोग प्रारंभ हुआ। ऊनी वस्त्रों के टुकड़े मिस्र वैबिलोन की कब्रों, पुरातन ब्रिटेन निवासियों के झोपड़ों के साथ मिले हैं। रोमन आक्रमण से पहले भी ब्रिटेन वासी इनका उपयोग करते थे। विंसेस्टर फैक्टरी ने ऊन का तरह-तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद इसका इंग्लैंड में खूब प्रयोग किया जाने लगा। हेनरी द्वितीय ने कानून, वस्त्रहाट और बुनकारी संघ बनाकर इस उद्योग को प्रोत्साहित किया। सन् 1788 में हार्टफोर्ड (अमेरिका) में जल-शक्ति-चालित ऊन फैक्टरी आरंभ हुई। ऊन सफेद, काले और भूरे रंग में ही मिलती है। पालतू भेड़ों की ऊन सफेद रंग की होती है। रंगीन ऊन सबसे अधिक पुरानी नस्ल की उन भेड़ों से मिली है, जो कालीन बुनने लायक मोटे किस्म की ऊन पैदा करती है।



अगर कोई छुपा बच्चा पीछे से जाकर उसे धप्पा कर दे तो डेन को फिर दोबारा डेन बनाना होता है।

स्टापू

इस खेल में जमीन में चौकोर बॉक्स जड़ा जाता है। फिर इनमें एक से दस तक गिनती लिखी जाती है। हर बच्चा एक-एक करके दस खानों में स्टापू फेंकता है। लंबड़ी करते हुए उस पत्थर तक पहुंचना होता है और उसे पैर से खिसकाते हुए वापस लाना होता है। इस गेम से ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है और हमारे पैर बेहद मजबूत होते हैं।

स्पाइंग गेम्स

ये चोर-पुलिस की तरह का गेम होता है। इसमें दो टीम होती हैं। एक टीम चोर बनाती है तो दूसरी पुलिस। पुलिस वाली टीम चोर वाली टीम को खोज कर उसे कैद करती है।

क्रिकेट

इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट के पहले वलब की स्थापना 1787 में हुई थी और पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। शुरुआत में क्रिकेट में टेस्ट मैच ही खेला जाता था, वनडे मैच की शुरुआत 1971 में हुई। पहला वनडे मैच भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला गया था। तुमने आईसीसी का नाम तो जरूर सुना होगा। आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय मैच होते हैं, सभी की रूपरेखा आईसीसी निर्धारित करती है और वर्ल्ड कप का आयोजन करती है। अब तक क्रिकेट का वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा पांच बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, वहीं भारत दो बार विश्व विजेता बना है।

ये होंगे फायदे

आउटडोर गेम्स से हमें कई नए दोस्त मिलते हैं, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं और जिनसे स्कूल आने-जाने, होमवर्क और इनडोर गेम्स में बिजी रहने की वजह से हम मिल नहीं पाते। इसके अलावा, बाहर निकल कर खेलने से पढ़ाई और आसपास की तमाम दूसरी चीजों के बारे में सीख सकते हो। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आउटडोर गेम्स से तुम्हारा शरीर चुस्त रहेगा, भूख ज्यादा लगेगी और तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे। इन गेम्स में कई ऐसे गेम्स भी हैं, जिनमें एक्सपर्ट होने पर तुम उस गेम की डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल टीम में चुने जा सकते हो, जैसे बैडमिंटन, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल। आउटडोर गेम्स से एक बेहतर कैरियर भी मिल सकता है।



जब से कंप्यूटर आया है, तब से बाहर जाकर खेलने की तो जैसे फुरसत ही नहीं मिलती तुम बच्चों को। पर क्या तुम जानते हो कि आउटडोर खेल तुम्हारे संपूर्ण विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या खेलोगे, किसके साथ और कब...यह सब आज हम तुम्हें बता रहे हैं।



हॉकी

हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ब्लेकहीथ एवी एंड वलब को हॉकी का पहला संगठित वलब माना जाता है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। हॉकी का पहला इंटरनेशनल मैच 1895 में वेल्स और इंग्लैंड के बीच खेला गया था और पहला वर्ल्ड कप 1971 में पाकिस्तान और स्पेन के बीच खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने खिताब अपने नाम किया था। जानते हो, ओलंपिक में सबसे ज्यादा आठ बार भारत ने हॉकी का मैच जीता है।



फुटबॉल

तुममें से काफी बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद होगा। जानते हो इस खेल का जन्मदाता भी इंग्लैंड ही है। भारत में अंग्रेज इस खेल को लाए और यहां के लोगों को खेलना सिखाया। फुटबॉल का पहला वलब 1857 में स्थापित किया गया। इसका नाम शोफील्ड फुटबॉल वलब था। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा है। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप वर्ष 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था, जिसमें उरुग्वे विजेता घोषित किया गया।

टेबल टेनिस

इस खेल का जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ था। वर्ष 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई।



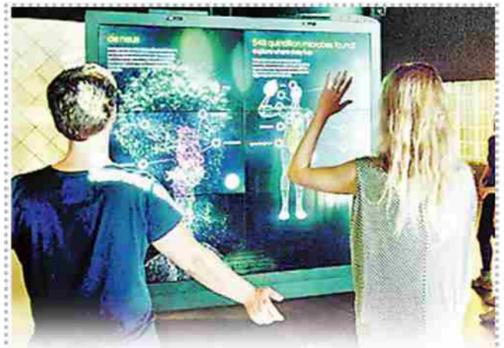
इसका पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 1927 में खेला गया।

वॉलीबॉल

वॉलीबॉल का जन्मदाता यूएसए है। 1895 में इसकी शुरुआत हुई। वॉलीबॉल की प्रमुख संस्था इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना 1948 में हुई और पहला वर्ल्ड कप 1949 में हुआ। तो तुम भी खेलो इसे दोस्तों के साथ।

बास्केटबॉल

इस खेल का जन्म अमेरिका में हुआ था। 1891 में जेम्स नेरिस्म नामक अमेरिकी ने इसे खेलना शुरू किया। पहला मैच 1930 में खेला गया। बास्केटबॉल की सर्वोच्च संस्था



नीदरलैंड में है दुनिया का पहला माइक्रोब जू

नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में दुनिया का पहला माइक्रोब जू यानी सूक्ष्म जीव 'वाटिका' खुला है। माइक्रोपिया नामक इस जीव-जंतु वाटिका को शहर के उस जंतु पार्क 'आर्टिस' में खोला गया है जिसकी स्थापना 176 साल पहले हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी जीव-जंतु वाटिकाओं में से एक है।

140 वर्ष पुरानी इमारत में रखा एक खूबसूरत भूरे रंग का बक्सा बैक्टिरिया, फंगस, कार्डी तथा अन्य एक कोशिका वाले जीवों का आवास है। ये वे जीव हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता परंतु धरती पर जीवन इनसे ही संभव है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि सूक्ष्म जीवों में से केवल 1 प्रतिशत के बारे में ही आज तक इंसान जान सका है। कई लोगों के लिए सूक्ष्म जीव नफरत व भय की भावनाएं पैदा करते हैं। दरअसल, यह डर उस चीज से है जिसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है और लोगों के मन से सूक्ष्म जीवों के बारे में इसी डर को दूर करना इस जीव-जंतु वाटिका का पहला मकसद है। हेग कहते हैं कि यदि हम प्रकृति को जानना चाहते हैं तो हमें सूक्ष्म जीवों को भी जानना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान इन सूक्ष्म जीवों से बेशक नफरत करता हो लेकिन हर

इंसान का शरीर अरबों सूक्ष्म जीवों का घर होता है। केवल इंसानों की एडी में ही 80 प्रकार के अलग-अलग सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने शरीर का बॉडी स्कैन करावा कर देख सकता है। चाहे तो यहां एक अन्य दिलचस्प तरीका भी है। एक जगह फर्श पर लाल रंग का दिल बना है। जैसे ही यहां खड़े होकर कोई जोड़ा एक-दूसरे का चुम्बन लेता है, करीब लगे 'किस' मीटर की स्क्रीन पर नम्बर बढ़ते जाते हैं, जब तक कि मीटर में से संदेश न आने लगे कि 'आप दोनों ने अभी 10 लाख सूक्ष्म जीवों का आदान-प्रदान किया है।' माइक्रोपिया में दिखाया जाता है कि सूक्ष्म जीव कैसे जीते हैं, कैसे भोजन करते हैं और कैसे प्रजनन करते हैं? बैक्टिरिया इतने छोटे होते हैं कि एक सूई की नोक पर 10 लाख बैक्टिरिया आराम से समा सकते हैं। डच विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञानी इन धारणाओं पर 12 साल से अधिक वक्त से माथापच्ची कर रहे हैं। यहां उन सूक्ष्म जीवों को प्रदर्शित किया गया है जो कृत्रिम वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले एड्स वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों को केवल मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए यहां माइक्रोस्कोप के लेंस के साथ जोड़ा गया एक थ्री डी टैलीस्कोप है, जो नंगी आंखों से न दिखने वाले सूक्ष्म जीवों को हजार गुणा बड़ा करके दिखाता है।

इनका रखो ध्यान



- आउटडोर गेम्स के साथ इतनी सारी अच्छी बातें जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन बातों का ख्याल रखने पर ही आउटडोर गेम्स खेल कर भी तुम पढ़ाई को और परिवार को पूरा टाइम दे सकते हो।
- सबसे पहले तो खेलने के लिए ऐसी जगह चुनो, जो घर के आसपास हो, यानी जहां से घर वाले तुम्हें आवाज देकर बुला सकें। अगर आसपास खेलने की जगह नहीं है तो अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ करीब की किसी जगह पर खेलने जा सकते हो, लेकिन रोज नहीं। और इस जगह के बारे में घर वालों को पता भी होना चाहिए।
- ऐसे दोस्तों के साथ खेलना शुरू करो, जिन्हें तुम पहचानते हो या जो तुम्हारे ही जैसे हों। बाहर खेलने का यह मतलब नहीं है कि तुम इनडोर गेम्स को पूरी तरह गुड़बाय कह दो, क्योंकि एक तो इनसे भी तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है, दूसरे आउटडोर गेम्स रोज नहीं खेले जा सकते।
- ज्यादातर ऐसे गेम्स के लिए टीम की जरूरत पड़ती है और कभी-कभी दोस्तों का बाहर आकर खेलने का मन नहीं होता। अगर इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हें आउटडोर गेम्स के बहाने एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। नए दोस्त बनेंगे, फिजिकल फिटनेस रहेगी और कई सारी नई बातें भी सीख सकोगे। तो फिर देर किस बात की है, तुम अपने आसपास के दोस्तों के साथ मिल कर गेम प्लान करो और खेलने के लिए तैयार हो जाओ।

ब्रिटेन में सिख सैनिकों को सरकार देगी नितनेम गुटका

लंदन। ब्रिटेन के 100 साल के इतिहास में पहली बार सिखों की दैनिक प्रार्थना का गुटका, जिसका नाम नितनेम है। रक्षा मंत्रालय द्वारा सिखों की आस्था और विश्वास को देखते हुए, सिख सैनिकों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ब्रिटिश सेना में शामिल मेजर दलजिंदर सिंह विरदी इसके लिए 2 साल से प्रयासरत थे। ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय ईसाई सैनिकों को ईसाई धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध कराता है। सिखों को नियमित प्रार्थना के लिए नितनेम गुटका नहीं मिलता था। लंदन में केंद्रीय गुरुद्वारा मंदिर के पुस्तकालय सैनितनेम गुटक लेकर ब्रिटिश सिख सैन्य कर्मियों के बीच में बांटा गया है। ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार सिख सैनिकों को सिख धर्मग्रंथ पढ़ने की आस्था को ध्यान में रखते हुए, यह कदम उठाया है।

ईरान में हालात को लेकर विशेष सत्र आयोजित करेगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई, पत्रकारों को धमकिया और मानवाधिकार उल्लंघन के अन्य मामलों के मद्देनजर विशेष सत्र आयोजित करने जा रहा है। आयोग जर्मनी और आइसलैंड के राजनियक अनुरोध पर 24 नवंबर को यह सत्र आयोजित किया जा सकता है। जर्मनी ने शुक्रवार को आयोग को एक पत्र भेजा था, जिसमें 'ईरान में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति से निपटने' के लिए विशेष सत्र आयोजित करने का अनुरोध किया गया था। आयोग के 47 सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई नई इस अनुरोध का समर्थन किया है। ईरान में 16 सितंबर को धर्माचार पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस दौरान ईरान में कथित तौर पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। 'ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स' नामक निगरानी समूह के अनुसार ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 328 लोगों की मौत हो चुकी है और 14,825 अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है।

चीन ने कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की

बीजिंग। चीन ने कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने की शुरुआत करते हुए देश में आने वाले यात्रियों के लिए पृथक्काय की अवधि में कटौती की है और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू प्रतिबंध हटा दिया है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की नवनिर्वाचित सात सदस्यीय स्थायी समिति की पहली बैठक के बाद नए नियमों की घोषणा की गई। सीपीसी की यह बैठक बुधवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने की। स्थायी समिति सीपीसी का सर्वोच्च नीति-निर्माण और कार्यान्वयन निकाय है। चीन ने कोविड-19 के मरीजों के निकट संपर्क में आने वाले लोगों की पृथक्काय की अवधि को 10 दिन से घटाकर आठ दिन कर दिया है। इसमें व्यक्ति को पांच दिनों तक पृथक्काय केंद्र में अनिवार्य रूप से रहना होगा, जिसके बाद तीन दिनों तक घर पर ही उसके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। चीन के सरकारी समाचार-पत्र ग्लोबल टाइम्स ने शुक्रवार को टीवी कर कहा कि "सर्किट ब्रेकर" नीति के तहत यदि चीन आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया तो उसे किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। "सर्किट ब्रेकर" नीति के तहत यदि कोई यात्री आगमन पर कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है तो चीनी विमानन अधिकारी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आगमन पर तबे समय के लिए निलंबित कर देते हैं। "सर्किट ब्रेकर" नीति के कारण कई विमानन कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कारण भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान को बालक करने में रुकावट आ रही थी। इस बीच, चीन में बुधवार को कोविड-19 के 1,150 नए मामले सामने आए। इसके अलावा विभिन्न शहरों में 9,358 ऐसे मामले पता चले हैं जो स्थानीय हैं और लोगों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं।

अटलांटा में श्री श्री रविशंकर को दिया गया 'गांधी पीस पिलग्रिमेज' पुरस्कार

वाशिंगटन। भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर को महात्मा गांधी एवं डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शांति एवं अहिंसा के संदेशों का प्रसार करने में उनके अथक प्रयासों के लिए अटलांटा में 'गांधी पीस पिलग्रिमेज' पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर को डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के भतीजे इसाक फारिस और अटलांटा में भारत की महावाणिज्य दूत डॉ. स्वाति कुलकर्णी की उपस्थिति में अमेरिका के गांधी फाउंडेशन ने यह प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि दुनिया में जो बदलाव हम देखना चाहते हैं, उसके प्रति विवेक, अंतर्दृष्टि तथा गांधी-किंग के शांति एवं अहिंसा के उपदेशों से प्रेरित होकर मानवता की सेवा करने को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर ने अपने संदेश में कहा कुछ संदेश कालांतरित संदेश होते हैं। इस श्रेणी में मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी के संदेश बहुत प्रासंगिक हैं। वे हर पीढ़ी में हर उम्र के लिए बिल्कुल नए हैं। कभी-कभी यह और प्रासंगिक हो जाते हैं। आज की दुनिया में, जहां हम ऐसी धुंधलीकरण एवं तनाव से जूझ रहे हैं, शांति का संदेश ऊंचा एवं स्पष्ट होना चाहिए।

अफ्रीकी राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए धन उपलब्ध कराने पर जोर दिया

जिनेवा अफ्रीकी महाद्वीप के नेताओं और वार्ताकारों ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, धूल भरी आंधी, बाढ़, जंगल में आग, तटीय भू-क्षरण, चक्रवात और अन्य मौसमी परिवर्तनों का सामना कर रहे इस महाद्वीप को इसका मुकाबला करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए उस धन की आवश्यकता है। मिस्र में हो रहे सीओप27 सम्मेलन में अफ्रीकी समूह के वार्ताकारों के लिए यह विषय मुख्य प्राथमिकताओं में एक है। समूह के अध्यक्ष इफ्रेम शितिमा ने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप के लिए वार्ताओं के नतीजों को कार्रवाई में तब्दील होते देखने को इच्छुक है, जहां लायों लोग जलवायु से जुड़ी आपदाओं को सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन को महाद्वीप के लाखों लोगों को समाधान उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफ्रीका को प्रतिकूल मौसम के प्रति अनुकूलता और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने तथा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए धन की जरूरत है। विश्व बैंक के एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु से जुड़ी घटनाएं विश्व भर में 13.2 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल देगी। साथ ही, अफ्रीकी देशों को 2050 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 10 से 15 प्रतिशत गंवाना पड़ जाएगा। अफ्रीका की पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन में महज चार प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जबकि महाद्वीप में विश्व की 17 प्रतिशत आबादी है। जलवायु से जुड़ी आपदाओं और स्थिति बदतर होने से रोकने के लिए ढलने के वास्ते जलवायु वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। एक साल में 100 अरब डॉलर के जलवायु वित्तपोषण का वादा पूरा किया जाना बाकी है, जबकि इसकी समझ-सौदा को पार हुए दो साल हो गये हैं। संश्लेष के राष्ट्रपति वावेल रामकलानन ने कहा कि छोटे द्वीपीय देशों के गठबंधन के नेता भी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए नये सिर से धन की मांग कर रहे हैं।

एंटिगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री ने की मांग-सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने के लिए मुआवजा दें भारत और चीन

काहिरा। द्वीपीय देश एंटिगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री ने मांग की कि बड़े पैमाने पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन की ज़रूरत से आने वाली आपदाओं के बाद देशों के पुनर्निर्माण के लिए जलवायु मुआवजा देना चाहिए। बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले देशों में चीन और भारत भी शामिल हैं। छोटे द्वीप देशों के गठबंधन ने मिस्र के शर्म अल-शेख में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कोष-27 के दौरान भारत और चीन से मुआवजे की मांग की है।



बोलोविया में 2025 में होने वाले चुनाव से पहले अधिकारियों द्वारा अगले साल जनगणना कराने की मांग को लेकर सांताक्रूज़ में हड़ताल के दौरान एक जलते हुए बैरिकेड के बगल में खड़े प्रदर्शनकारी।

पाकिस्तान में होगा नया आगाज? वतन वापसी करेगें नवाज, क्या समय से पहले होने वाले हैं चुनाव

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो नवाज शरीफ लंदन में अपना निर्वासन समाप्त कर अगले आम चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए दिसंबर में देश लौट सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इससे पहले ये खबर सामने आई कि 72 वर्षीय तीन बार के पूर्व प्रधा मंत्री नवाज को पीएमएल-एल पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा एक राजनयिक पासपोर्ट दिया गया था। इस मामले से वाकिफ पीएमएल-एल पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने भरोसा जताया है कि शरीफ दिसंबर में वतन वापसी कर सकते हैं।

क्या मध्यवर्धि चुनाव के लिए राजी हो गए शरीफ ?

द एक्सप्रेस टिप्पण अखबार ने पार्टी के सूत्र के हवाले से नाम न छपाने की शर्त पर कहा कि यह अफवाह है कि शरीफ चुनाव के करीब ही चुनाव प्रचार के लिए लौटेंगे, सच नहीं है क्योंकि उनकी वापसी का मतलब यह नहीं है कि पीएमएल-एल जल्द चुनाव के लिए राजी हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री 2019 से लंदन में स्व-निर्वासन में रह रहे हैं। दिसंबर 2018 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी।



क्या है पीएमएल की योजना ?

पार्टी जल्द चुनाव के मामले में नहीं मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पीएमएल-एन, भले ही वह अपनी सरकार गंवा दे, इस मांग को नहीं मानेगा, और यह फाइनल है। हालांकि उन्होंने कहा कि बड़े शरीफ की वापसी एक जन संपर्क अभियान की शुरुआत होगी,

जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम सम्मेलन और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी रिंग वोटों को वापस लाने के लिए शेष कार्यकाल का पूरा उपयोग करने की कोशिश करेगी।

अमेरिका ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर किया

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। अमेरिका ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। अमेरिका ने यह घोषणा तब की है, जब ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नई दिशे में थीं। विभाग ने काग्रेस को एक रिपोर्ट में निर्णय से अवगत कराया, जिसमें कहा गया था कि भारत सूची में बने रहने की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी निगरानी सूची से हटा दिया गया है, जबकि चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान इस पर बने हुए हैं। भारत ने दो रिपोर्टिंग अवधियों में तीन मानदंडों में से एक को पूरा किया, जिससे यह हटाने के योग्य हो गया, जैसा कि चार अन्य देशों ने किया था। रिपोर्ट का विमोचन येलेन की भारत यात्रा के दौरान व्यापार बंधनों को मजबूत करने के लिए किया गया था, क्योंकि चीन पर अधिक निर्भरता से समस्याओं का सामना करने के बाद अमेरिका वैश्विक आर्थिक और विनिर्माण पुनर्गठन चाहता है। येलेन ने फंडेशोरिंग की अवधारणा की बात की मित्र देशों में आपूर्ति श्रृंखला लाना।

उन्होंने कहा-पेसी दुनिया में जहां आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां लागत बढ़ा सकती हैं, हमारा मानना है कि भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। भारत हमारे भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों में से एक है। किसी देश को निगरानी सूची में रखने के लिए जिन तीन कारकों पर विचार किया गया है, वह हैं अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष का आकार, चालू खाता अधिशेष और विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार एकतरफा हस्तक्षेप। इसके अलावा, यह मुद्रा विकास, विनिर्माण दर प्रथाओं, विदेशी मुद्रा आरक्षित कवरेज, पूंजी नियंत्रण और मौद्रिक नीति पर भी विचार करता है। रिपोर्ट में विशेष रूप से यह नहीं बताया गया है कि भारत किन मानदंडों को पूरा करता या नहीं करता है, लेकिन इसमें संबंधित क्षेत्रों में नई दिशे के प्रदर्शन का उल्लेख है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 526.5 अरब डॉलर था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 16 फीसदी है। भारत, रिपोर्ट में शामिल अन्य देशों की तरह, मानक पर्याप्तता बेंचमार्क के आधार पर पर्याप्त या पर्याप्त से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना जारी रखता है।

यूक्रेन के विदेश मंत्री संग एस जयशंकर की मुलाकात, जंग के माहौल में परमाणु खतरों पर हुई बात

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन से इतर यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा सहित अपने समकक्षों से मुलाकात की और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अनाज की पहल और परमाणु चिंताओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने टीवी करते हुए कहा कि दमित्रो कुलेबा से मिलकर खुशी हुई। हमारी चर्चा में संघर्ष, अनाज की पहल और परमाणु चिंताओं में हालिया घटनाक्रम शामिल थे।



भारोदारी को निलंबित करेगा, लेकिन समाप्त नहीं करेगा। यह सौदा काला सागर के माध्यम से यूक्रेनी अनाज के निर्यात के लिए एक सुरक्षित मानवीय गलियारा प्रदान करता है, जो 'रोटी की

टेकरों' से जूझ रहे भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण लंबी खाद्य कीमती से निपटने के लिए है। इस बीच, पुतिन ने परमाणु हमले को लेकर अपनी बयानबाजी तेज कर दी, जिससे यह

पाकिस्तान के नये सेना प्रमुख की नियुक्ति पर किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगे शरीफ बंधु

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ के बीच लंदन में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकार सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर इमरान खान सहित किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। शुक्रवार को मीडिया में आयी खबर में यह जानकारी दी गयी है। डॉन अखबार की खबर के अनुसार, शहबाज शरीफ ने इस सप्ताह पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) प्रमुख नवाज शरीफ से भेंट की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की जल्द चुनाव कराने की मांग को न मानने का निर्णय किया। खबर में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि शरीफ बंधुओं का कहना है कि सेना प्रमुख की नियुक्ति का अधिकार देश के प्रधानमंत्री के पास है और इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। पीएमएल-एन के एक अंदरूनी सूत्र के हवाले से खबर में कहा गया है कि सेना प्रमुख की नियुक्ति और नये चुनावों के मुद्दे पर शहबाज की सरकार पर कुछ क्षेत्रों से दबाव था, यही कारण है कि प्रधानमंत्री को पार्टी प्रमुख के साथ इस पर चर्चा करनी पड़ी कि क्या इन मांगों को स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। सूत्रों ने यह भी बताया कि बैठक के दौरान जनरल बाजवा के सेवा विस्तार की संभावना पर भी चर्चा हुई। जनरल बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

इस माह 8 अरब हो जाएगी पृथ्वी की जनसंख्या

लंदन (एजेंसी)। इस माह धरती पर इंसानों की आबादी 8 अरब की संख्या को पार कर जाएगी। मानव प्रजाति का उद्भव पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले हुआ था। तब से संसार में मानव जनसंख्या बीच-बीच में कुछ रुकावटों के बावजूद बढ़ती ही जा रही है, जिसमें उल्लेखनीय जनसंख्या विस्फोट 19वीं सदी के बाद ही देखने को मिला है। मानव जनसंख्या का यहाँ तक पहुँचना कोई सरल सीधी घटना नहीं है।

जीवाणुओं से मिली जानकारी बताती है कि सबसे पहला मानव 28 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में रहता था। तब से अब तक के इतिहास के प्रमाण यही बताते हैं कि मानव जनसंख्या ने तमाम तरह की आपदाओं और समस्याओं को झेलते

हुए बढ़तेचरी ही की है और 20वीं सदी में तो ऐसा जनसंख्या विस्फोट देखने मिला है कि आज हम 8 अरब हो गए हैं। फिर भी यह सच ही है कि हमारे पास 19वीं सदी से पहले की जनसंख्या के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे सही तस्वीर नहीं मिलती है। हम जो जानते हैं उससे भी काफी कुछ पता चलता है। शुरू में मानव शिकारी और खाद्य सामग्री जमा करने का काम ही करते थे। उनके कम बच्चे हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि शिकारी और खाद्य सामग्री जमा करने वाली जीवन पद्धति के चलते उन्हें अपने भोजन की जरूरतों के चलते उन्हें बहुत बड़े इलाकों की जरूरत होती थी जो एक व्यक्ति के लिए करीब 10 वर्ग किलोमीटर के बराबर हुआ करता

था। लेकिन जैसे ही इंसान बस्ती में बसना शुरू हुआ सभ्यता के साथ-साथ दुनिया की जनसंख्या भी बढ़ने लगी। समय के साथ केवल धीरे-धीरे ही जनसंख्या रही। इस बढ़ती जनसंख्या में सबसे बड़ा योगदान खेती का ही था क्योंकि उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के भोजन की समस्या निपटने में मदद मिली। खेती से भोजन का भंडारण संभव हो गया और लोगों को पोषण वाला भोजन भी मिलने लगा जिससे जन्मदर भी बढ़ने लगी क्योंकि महिलाएँ सेहतमंद रहने लगीं और उन्हें बच्चा पैदा करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। लेकिन स्थायी बसाहट से कई तरह की समस्याएँ भी आईं। पालतू जानवरों के रखने से कई तरह की बीमारियाँ भी आईं। उस दौर में बच्चों



के मरने की दर ज्यादा थी। एक तिहाई बच्चे साल भर के अंदर मार जाते थे और दूसरे एक तिहाई 18 साल की उम्र से पहले। अनुमानों के अनुसार दस हजाह ईसा पूर्व में 60 लाख की जनसंख्या से 2000 ईसापूर्व तक जनसंख्या करीब 10 करोड़ और उसके बाद पहली ईस्वी के बाद 25 करोड़ हो गई। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ में यूरोप सहित दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा जनसंख्या साफ करने का काम किया। इसकी वजह से 1300 की करीब 43 करोड़ की जनसंख्या केवल 37 करोड़ हो गई। इसके बाद कई सदियों तक कभी महामारी तो कभी युद्धों ने दुनिया की आबादी घटने का काम किया। 19वीं सदी में जनसंख्या में विस्फोट देखने को मिला, जिसके चिकित्सा विज्ञान और

कृषि का औद्योगिकरण प्रमुख कारण थे। 1800 से दुनिया की जनसंख्या 8 गुना बढ़ गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी प्रमुख जीवन रक्षक दवाइयाँ और टीकों का विकास है। इसमें चेचक का टीका सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा 1970 और 1980 के दशक में एक ही क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। हृदय कि चिकित्सा में उपचारों की सफलता ने मृत्यु दर में भी भारी कमी कर दी। ऐसी ही वजहों से दुनिया 1975 में 4 अरब, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब, 2011 में 7 अरब और अब इसी महीने 8 अरब की हो रही है।

बोरिस जॉनसन ने उड़ाई पुतिन की खिल्ली, उन्हें 'मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा' करार दिया

लंदन। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर खिल्ली उड़ाई है। बोरिस जॉनसन ने पुतिन को 'मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा' करार दिया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं लगता कि हम इस बारे में चिंता करने की जरूरत है कि पुतिन अपनी हार कैसे मानेंगे। आश्चर्यकर वह प्रोपेगेंडा के उस्ताद हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि दुनिया के केवल एक नेता पुतिन ने ही बीजिंग ओलंपिक को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने कहा कि पुतिन शी जिनपिंग के पंक है। यूक्रेन युद्ध पर बोरिस जॉनसन ने कहा पुतिन यह लड़ाई हार जाएंगे और वह इसी लायक हैं। पुतिन को नहीं पता कि वह ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। इस हार से रूस की ताकत कमजोर होगी और चीन को मजबूती मिलेगी। युद्ध के चलते दुनिया भर में मिलिट्री एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। हम खतरनाक समय में जी रहे हैं और निरंकुश शासकों के गैर जिम्मेदार और खतरनाक व्यवहार के खिलाफ ब्रिटेन और भारत को साथ आना होगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा मैं वेस्ट लंदन में अपनी सीट से प्रतिनिधित्व जारी रखूंगा। मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं। मैं किताने भी लिख रहा हूँ। जिन चीजों के प्रति मेरा विश्वास है, उन्हें लेकर अपने प्रयास बंद नहीं करूंगा। यूक्रेन के लोगों के प्रति हमारा समर्थन जारी रहेगा। यूक्रेनी जनता को आक्रमण से बचाने के लिए हमारी मदद जारी रहेगी।

खेरसॉन से हुई सभी रूसी सैनिकों की वापसी, अब एक भी सैन्य इकाई वहां नहीं बची : दिमित्री पेस्कोव

माइकोलैव (एजेंसी)। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन के दक्षिणी खेरसॉन क्षेत्र में नौपर नदी के पश्चिमी किनारे से अपने सभी सैनिकों को वापसी पूरी कर ली है। यह कदम यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के लिए एक और झटका माना जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार सुबह सैनिकों की वापसी पूरी की गई है और अब एक भी सैन्य इकाई वहां नहीं बची है। जिन क्षेत्रों से रूस की सेना ने वापसी की है, उनमें खेरसॉन शहर भी शामिल है। यह एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी है जिस पर रूसों ने यूक्रेन पर अपने हमलों के दौरान कब्जा किया था।

हालांकि रूस बचाव की मुद्दा में रहा और जोर देता रहा कि सैनिकों की यह वापसी किसी भी तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाली नहीं है। क्रैमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि माइकोलैव भी खेरसॉन क्षेत्र को रूस के हिस्से के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि क्रैमलिन को करीब एक महीने पहले खेरसॉन और तीन अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों पर अवैध कब्जे की खुशी मनाने पर कोई अफसोस नहीं है। रूस की सैनिकों को वापसी की इस घोषणा से कुछ देर पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की के कार्यालय ने खेरसॉन क्षेत्र की स्थिति को 'मुश्किल' कहा था। खबर है कि रूस ने उन कुछ गांवों और शहरों पर गोलाबारी की है जिन पर यूक्रेन के सैनिकों ने खेरसॉन क्षेत्र में अपने अभियान के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में फिर से नियंत्रण प्राप्त किया है। यूक्रेन के अधिकारियों को रूसी सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद आशंका है कि ये सैनिक खेरसॉन शहर में घात लगाकर हमलों में शामिल हो सकते हैं। सैन्य विश्लेषकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया था कि रूस की सेना को सैनिकों की वापसी पूरी करने में कम से कम एक सप्ताह लगेगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2022 को आज मिलेगा नया विजेता, बारिश ने धोया मैच तो जानें क्या होगा

आईसीसी के दोबारा अध्यक्ष बने ग्रेग बार्कले, जय शाह को भी मिली अहम जिम्मेदारी

नई दिल्ली (एजेंसी)।



न्यूजीलैंड की ग्रेग बार्कले को सर्वसम्मति से एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया चेयरमैन चुन लिया गया। ग्रेग बार्कले का यह दूसरा कार्यकाल है। इसके अलावा बीसीसीआई के सचिव जय शाह को भी आईसीसी में ताकतवर पद मिला है। जय शाह वित्त और वाणिज्य मामलों की समिति के प्रमुख होंगे। बार्कले का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। जिम्मेदारी के तालेवा मुकुहलानी ने अपना नाम वापस ले लिया था जिसके बाद से बार्कले को निर्विरोध चुना गया। आईसीसी की ओर से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। अपनी नियुक्ति के बाद बार्कले ने यह भी कहा है कि आईसीसी का फिर से चेयरमैन चुना जाना भरे लिए सम्मान की बात है। मैं समर्थन करने वाले लोगों को शुक्रिया करना चाहूंगा।

जय शाह को करें तो शाह को आईसीसी की सबसे महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। यह समिति सभी बड़े वित्तीय नीतिगत फैसले करती है जिसके बाद आईसीसी बोर्ड इन्हें मंजूरी देता है। सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक सदस्य ने जय शाह को वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख के तौर पर स्वीकार कर लिया। आईसीसी चेयरमैन के अलावा यह समान रूप से ताकतवर उप समिति है। इस समिति के काम में सदस्य देशों के बीच राजस्व साझा करना शामिल है। वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख हमेशा आईसीसी बोर्ड सदस्य होता है और शाह का चुना जाना स्पष्ट करता है कि वह आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस समिति के प्रमुख का पद एन श्रीनिवासन के दौर में भारत का हुआ करता था लेकिन गांगुली को इस पद के लिए आगे किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको लेकर देश में बीसीसीआई की ताकत काफी कम हो गयी थी।

न्यूजीलैंड की ग्रेग बार्कले को सर्वसम्मति से एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया चेयरमैन चुन लिया गया। ग्रेग बार्कले का यह दूसरा कार्यकाल है। इसके अलावा बीसीसीआई के सचिव जय शाह को भी आईसीसी में ताकतवर पद मिला है। जय शाह वित्त और वाणिज्य मामलों की समिति के प्रमुख होंगे। बार्कले का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। जिम्मेदारी के तालेवा मुकुहलानी ने अपना नाम वापस ले लिया था जिसके बाद से बार्कले को निर्विरोध चुना गया। आईसीसी की ओर से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। अपनी नियुक्ति के बाद बार्कले ने यह भी कहा है कि आईसीसी का फिर से चेयरमैन चुना जाना भरे लिए सम्मान की बात है। मैं समर्थन करने वाले लोगों को शुक्रिया करना चाहूंगा।

आपको बता दें कि बार्कले पहली बार 2020 में आईसीसी के चेयरमैन बने थे। इससे पहले भी न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन और 2015 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के निदेशक भी रह चुके हैं। बार्कले को बीसीसीआई का भी समर्थन हासिल था। हालांकि, पहले खबर आई थी कि सौरव गांगुली को इस पद के लिए आगे किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको लेकर देश में राजनीति भी खूब हुई। बात अगर

परवीन ने एशियाई चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण, मीनाक्षी को रजत

संकेत। अभी तक रेफरी को दिया जाने वाला वेतन बहुत कम है। राज्य लीग में एक रेफरी को 2500 से 5000 रुपये और राष्ट्रीय लीग में 8000 से 10,000 रुपये तक मिलते हैं। यह सालाना कई लाख रुपये से तीन लाख रुपये होते हैं जिसमें जीवन यापन कठिन रहता है। एआईएफएफ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा कि रेफरी के स्तर में तभी सुधार किया जा सकता है। जब रेफरी को पर्याप्त पैसा मिले जिससे वह अपने प

थापा ने एशियाई चैंपियनशिप में जीता रजत



अम्मान। भारतीय मुक्केबाज शिवा थापा ने एएसबीसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में रविवार को रजत पदक हासिल किया। थापा का सामना पुरुषों के 63.5 किग्रा फाइनल में उजबेकिस्तान के अब्दुल्लाएव से था, लेकिन बाउट के दौरान थापा को चोट लगने के कारण रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। रजत पदक जीतने वाले थापा चैंपियनशिप के 2022 संस्करण में भारत के सबसे सफल पुरुष मुक्केबाज हैं, जबकि इससे पहले भारत के पांच पुरुष मुक्केबाज कांस्य पदक जीत चुके हैं।

टी20 विश्व कप की जीत से हमारी फुटबॉल टीम को फीफा विश्व कप में मिलेगी प्रेरणा: बटलर

मेलबर्न। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का कहना है कि अगर उनकी टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में जीत जाती है तो यह प्रदर्शन फीफा विश्व कप में उनके देश की टीम को प्रेरित करेगा। बटलर ने कप्तान के तौर पर अपनी पहली वैश्विक प्रतियोगिता में टीम को खिताबी मुकाबले में पहुंचा दिया है। यह पूछने पर कि क्या देश की फुटबॉल टीम क्रिकेट टीम से प्रेरणा ले सकती है तो मुद्रुभाषी कप्तान ने कहा, "बिलकुल, मुझे निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद है।" उन्होंने कहा, "इंग्लैंड की संस्कृति में खेल इतना अहम हिस्सा है और विश्व कप में टीमों को समर्थन देना इंग्लैंड में काफी होता है। आप भी निश्चित रूप से इस समर्थन को महसूस कर सकते हो।" इंग्लैंड फीफा विश्व कप में ग्रुप बी में ईरान, वेल्स और अमेरिका के साथ शामिल है।

ब्राजील अगले माह कतर में होने वाले विश्व कप फुटबाल में छठी बार बनेगा चैंपियन: पेले

रियो डी जेनेरियो। फुटबॉल में जीते जी किंवदंती बने पेले ने भविष्यवाणी की है कि ब्राजील अगले माह कतर में होने वाले विश्व कप में छठी बार चैंपियन बनेगा। ब्राजील ने 10 टीमों के दक्षिण अमेरिकी ग्रुप में अपराजित रहते हुए शीर्ष पर रहकर विश्व कप में जगह बनाई थी। ब्राजील ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहे अर्जेंटीना से छह अंक आगे रहा था। 82 वर्षीय पेले ने सोशल मीडिया पर टाका किया कि ब्राजील एक बार फिर फुटबाल विश्व कप ट्रॉफी जीतेगा। ब्राजील ने आखिरी बार विश्व कप 2002 में जीता था। वह अपने अभियान की शुरुआत 24 नवंबर को सर्बिया के खिलाफ करेगा। इस ग्रुप में स्कॉटलैंड और कैमरून भी शामिल हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से एक पेले तीन बार विश्व कप जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं।

एडिलेड (एजेंसी)।



टी20 वर्ल्ड कप 2022 अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। फाइनल मुकाबला रविवार 13 नवंबर को मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट के महामुकाबले पर दुनिया भर की नजरें रहने वाली है। फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा।

मुकाबले के दिन मेलबर्न में बारिश की 95 प्रतिशत संभावना रहने वाली है। इसमें 25 मिली मीटर तक बारिश होने की संभावना भी बताई गई है। हालांकि अगर इस दिन के कारण रद्द किया गया। वहीं अब फाइनल मैच में भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। बता दें कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले पर बारिश का साया होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक फाइनल

वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला नहीं होता है तो इसके लिए आईसीसी के नियम भी हैं। आईसीसी के नियम के मुताबिक इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ मैचों में डकवर्थ लुईस नियम से नतीजा निकाला जा सकता है ताकि एक टीम विजेता घोषित हो सके। हालांकि डकवर्थ लुईस नियम से नतीजा निकालने के लिए 10-10 ओवरों का खेल होना अनिवार्य होता है। ऐसे में अगर बारिश के चलते रविवार को फाइनल मुकाबला होता है तो दोनों ही टीमों को कम से कम 10 ओवर खेलने होंगे। अगर 10-10 ओवरों का खेल भी पूरा नहीं हो पाया तो खेल जहां से रुका था, वहीं से रिजर्व डे में शुरू होगा। वहीं अगर दोनों टीमों ने टॉस कर लिया तो इस गेम शुरू होना माना जाएगा।

पेसा है दोनों टीमों का आकलन

अगले टी20 वर्ल्ड कप में नहीं होने चाहिए कुछ सीनियर खिलाड़ी, नए लोगों का मिलना चाहिए मौका: सहवाग

नई दिल्ली (एजेंसी)।

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत की हार के बाद वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी टीम के निराशाजनक प्रदर्शन की जमकर निंदा कर रहे हैं। कुछ टीम की बेंचिंग पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि टी20 जैसे फॉर्मेट में कई सीनियर खिलाड़ी फिट नहीं बैठते। इस बीच भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वह आगेले विश्व कप में मौजूदा टीम के कुछ चेहरे नहीं देखना चाहते हैं। टी20 वर्ल्ड कप का आगला संस्करण 2024 में खेला जाएगा और सहवाग का मानना है कि इस वर्ल्ड कप के लिए भारत को अभी से ही एक युवा टीम तैयार करनी चाहिए। भारतीय पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज ने कहा मैं मानसिकता के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से खिलाड़ियों में बदलाव देना चाहता हूँ। मैं अगले विश्व कप में कुछ चेहरे नहीं देखना चाहता। यह 2007 टी20 विश्व कप में भी हुआ था। इतने सालों से खेलने वाले दिग्गज खिलाड़ी उस विश्व कप में नहीं गए थे। युवाओं का एक ग्रुप

गया और किसी को उनसे कोई उम्मीद नहीं थी और मैं अगले टी20 विश्व कप के लिए इसी तरह की टीम को देखना चाहता हूँ, कोई भी उनसे जीतने की उम्मीद नहीं करेगा लेकिन वह टीम भविष्य के लिए होगी। सहवाग ने इस दौरान किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर उनका इशारा उन खिलाड़ियों पर है जिनकी उम्र 30 के पार पहुंच गई है। इनमें कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, दिनेश कार्तिक समेत कुछ अन्य खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा यदि आप अभी अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तभी आप दो साल के समय में एक टीम बना पाएंगे। मैं अगले विश्व कप में कुछ नॉन-परफॉर्मिंग सीनियर्स को नहीं देखना चाहता। मुझे उम्मीद है कि चयनकर्ता ऐसे निर्णय लेंगे। समस्या यह है कि क्या ये चयनकर्ता अगले विश्व कप तक रहेंगे? एक चयन पैनल होगा, नया प्रबंधन, नया दृष्टिकोण तो क्या वे बदलाव करेंगे? लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर वे आगेले विश्व कप में जाते हैं इसी टीम और इसी दृष्टिकोण के साथ, तो परिणाम भी यही होंगे।

सेमीफाइनल में भारत की हार पर पहली बार बोले सचिन तेंदुलकर, एक मैच के आधार पर टीम का आकलन ठीक नहीं

एडिलेड (एजेंसी)।

टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार झेलने के बाद भारत का खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। 2007 के पहले टी20 विश्व कप में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। तब से टी20 विश्वकप का खिताब जीतना भारत के लिए सपना सा बनता जा रहा है। इन सबसे बीच सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का भी बयान सामने आया है। अपने बयान में सचिन तेंदुलकर ने साफ तौर पर कहा है कि एक मैच के आधार पर टीम के बारे में आकलन करना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि टीम की हार पर लगातार आलोचना हो रही है। कप्तान और खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहां तक कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर

खिलाड़ियों के लिए रिटायरमेंट की भी बात की जा रही है।

इन्हीं सबके बीच सचिन तेंदुलकर का यह बड़ा बयान सामने आया है। अपने बयान में सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम सेमीफाइनल में अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। गेंदबाजी भी बेहद निराशाजनक रही। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ इस मैच के आधार पर हमें टीम का आकलन नहीं करना चाहिए, हम नंबर-एक टी-20 टीम हैं जो हम लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बन पाए हैं। इससे पहले भारतीय की हार पर उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जीवन के भी। अगर हम अपनी टीम की सफलता का जश्न अपनी सफलता की तरह मनाते हैं तो हमें अपनी टीम की हार को भी सहने में सक्षम होना चाहिए। जीवन में दोनों साथ-साथ चलते हैं।

गाइडल वॉल ने की थी आलोचना

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान गाइडल वॉन ने कहा था कि भारत ने 2011 में घरेलू धरती पर विश्व कप जीतने के बाद कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है और सीमित ओवरों की क्रिकेट के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीम रही है। वॉन ने कहा था कि उनके पास केवल पांच ही गेंदबाजी विकल्प कैसे हो सकते हैं जब 10 या 15 साल पहले भारत के सभी शीर्ष बल्लेबाज थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सकते थे - सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग और यहां तक कि सौरव गांगुली? उन्होंने कहा कि कोई भी बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं करता इसलिये कप्तान के पास केवल पांच ही विकल्प थे। उनके (भारत) गेंदबाजी विकल्प बहुत कम हैं, उनकी बल्लेबाजी में भी गिरावट नहीं है और उनमें स्पिन रणनीति की भी कमी है।

आप उनसे उम्मीद करते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, अब उन्हें चिढ़ाए जिनहोंने मैच गंवा दिया: गंभीर

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की उम्मीदों को एक बार फिर बहुत बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ शर्मनाक हार के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले से बाहर हो गई है। सन 2007 में टी20 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम अबतक दूसरे खिताब के लिए तैयार रही है। व्त् आर्मी ने टी20 का पहला खिताब सन 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ जोहासबाग में जीता था। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के दृष्टिकोण पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ी गौतम गंभीर ने निराशा हाथ लगाने के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में टीम इंडिया के प्रशंसकों से कहा आप केवल उनसे उम्मीद करते हैं, जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं! इसलिए अब आप उन खिलाड़ियों को चिढ़ाए। एडिलेड ओवल में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल सस्ते में पवेलियन चलते बने। इसके बाद मैदान में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया।

इंग्लैंड के खिलाफ मैच में युजवेंद्र चहल को मौका नहीं देना टीम प्रबंधन की बड़ी गलती : रणधीर सिंह

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के मुकाबले भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद कई दिग्गज अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। इंग्लैंड ने नॉकआउट मुकाबले में भारत को 10 विकेट से पराजित कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को एडिलेड में क्यों मौका नहीं दिया गया। इस मुद्दे पर चहल के कोच रणधीर सिंह ने भी टीम मैनेजमेंट पर निशाना साधा है। दरअसल, युजवेंद्र चहल को पूरे वर्ल्ड कप में प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया। जबकि आर अश्विन, अक्षर पटेल को पूरे मैचों में मौका दिया गया। टीम मैनेजमेंट ने चहल को एक भी मुकाबले में प्रयोग नहीं किया। वहीं, इंग्लैंड की टीम ने आदिल रशीद को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया और वह भारत के लिए खतरनाक साबित हुए। कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल मुकाबले में युजवेंद्र चहल इंग्लैंड के लिए घातक साबित हो सकते थे। चहल के कोच ने अपने बयान में कहा चहल को प्लेइंग इलेवन में शामिल न करना टीम मैनेजमेंट का फैसला है। प्रबंधन वहीं फैसला लेता है जो टीम के हित में हो और बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलता है। जहां तक चहल की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रांडस्ल बड़े होते हैं। चहल बेटर्स को रीड करके फ्लाइंग करता है। वह एक्स फैक्टर साबित हो सकता था। बाकी टीमों ने लेग स्पिनर्स को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया।

आईसीसी ट्रॉफी जीतने का इंतजार हुआ और लंबा

- आईसीसी ट्रॉफी को जीते हुए भारतीय टीम को हो गए 9 साल

नई दिल्ली (एजेंसी)।



टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद उसके आईसीसी ट्रॉफी जीतने का इंतजार और लंबा खींच गया है। भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने मात देकर विश्व कप से बाहर कर दिया। आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए भारतीय टीम को 9 साल हो गए हैं। उसके बाद से टीम इंडिया को पिछले 8 साल में 7 बार नॉकआउट में हार मिली है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है क्या टीम इंडिया नई 'चोकर्स' टीम बनती जा रही है? टीम इंडिया के सेमीफाइनल में प्रदर्शन को लेकर चोतरफा आलोचना हो रही है। लोग अब इसे नई 'चोकर्स' टीम बता रहे हैं। इनमें दिग्गज कपिल देव भी शामिल हैं। विश्व विजेता टीम के कप्तान रहे कपिल देव भी टीम इंडिया के प्रदर्शन से निराश हैं। कपिल देव ने भी माना कि हम इन्हें चोकर्स कह

सकते हैं। 'चोकर्स' उस टीम को कहा जाता है जो बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। वर्ल्ड क्रिकेट में यह टैग साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के पास है जो वैसे तो द्विपक्षीय या किसी अन्य टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करती है लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट में आते ही यह टीम बड़े मैच का दबाव नहीं झेल पाती है। टीम इंडिया की बात करें तो, भारत ने आखिरी बार साल 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया था। टीम इंडिया ने तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में

आईपीएल के बाद कोई खिताब नहीं जीती है भारतीय टीम

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हुए पूछा है कि उन्हें आईपीएल खेलने से कोई लाभ मिला या नहीं। अकरम ने कहा, 'सबको लगा था कि आईपीएल से इंडिया को बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब से आईपीएल शुरू हुआ है। इंडिया ने एक बार भी टी20 विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक साक्षात्कार में सुना था कि इनके खिलाड़ी एक भी विदेशी लीग नहीं खेलते। अगर इनको एक लीग खेलने की अनुमति मिल भी जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा इनके रूख में।' आपको बता दें कि बीसीसीआई के नियम के अनुसार भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी किसी भी विदेशी लीग जैसे बिग बैश लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग आदि में भाग नहीं ले सकते हैं।

लवलीना, परवीन, स्वीटी और अल्फिया को एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा), परवीन हुड्डा (63 किग्रा), स्वीटी (81 किग्रा) और अल्फिया खान (81 किग्रा से अधिक) ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शुरुआत को स्वर्ण पदक जीते। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और 75 किग्रा भार वर्ग में पहली बार किसी टूर्नामेंट में भाग ले रही लवलीना ने उज्बेकिस्तान की रुजमतोवा सोखोबा पर 5-0 से सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल की जबकि परवीन ने जापान की किटो माई को इसी अंतर से हराया। इसके बाद स्वीटी और अल्फिया ने क्रमशः कजाकिस्तान की गुलसाया येरजान और जॉर्डन की इस्लाम हुसेली को हराकर स्वर्ण पदक जीते। स्वीटी ने येरजान को आसानी से हराया जबकि अल्फिया की प्रतिद्वंद्वी पहले राउंड

में अयोग्य घोषित किये जाने के कारण बाहर हो गईं। दूसरी तरफ मीनाक्षी ने एशियाई चैंपियनशिप में पदार्पण पर अपना अभियान फ्लॉपिस्ट वर्ग (52 किग्रा) में रजत पदक जीतकर समाप्त किया। यह जीत 25 वर्षीय लवलीना के लिए मनोबल बढ़ाने वाली रही क्योंकि तोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद वह खराब फॉर्म में चल रही थी। वह विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में शुरु में ही बाहर हो गई थी। अस्म की यह मुक्केबाज 69 किग्रा से 75 किग्रा में खेलने लगी थी क्योंकि उनका पिछला भार वर्ग पेरिस ओलंपिक में शामिल नहीं है। दोनों मुक्केबाजों ने सहज शुरुआत की और एक दूसरे को हराया करने के लिए आमंत्रित किया लेकिन लवलीना ने जल्द ही कुछ मददर मुकें जमाकर अपना दबदबा कायम कर दिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के हमले से बचने का भी प्रयास किया।

लवलीना हालांकि कुछ करारे मुकें जड़ने में सफल रही। उनका एक मुक्का इतना जबरदस्त था कि रेफरी को सोखीबा के लिए गिनती गिननी पड़ी। लवलीना का एशियाई चैंपियनशिप यह तीसरा पदक है। उन्होंने 2017 और 2021 में वेल्डरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीते थे। विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता परवीन राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं ले पाई थी लेकिन उन्होंने यहां चौथी वरीयता प्राप्त माई के खिलाफ दबदबा बनाए रखा और सर्वसम्मत फैसले से जीत दर्ज की। दोनों मुक्केबाजों ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत की लेकिन शीर्ष वरीयता प्राप्त परवीन ने जल्द ही दबदबा बना दिया और अपनी प्रतिद्वंद्वी पर दनादन कई मुकें जड़े। पहला राउंड गंवाने के बाद माई ने वापसी की कोशिश की लेकिन परवीन पूरी तरह से तैयार थी और उन्होंने उसे कोई मौका नहीं दिया। भारतीय मुक्केबाज ने तीसरे राउंड में अपने अपर कट का अच्छा



नमूना पेश किया। मीनाक्षी पूरी कोशिश के बावजूद स्वर्ण पदक के मुकाबले में जापान की किनोशिता रिंका से विभाजित फैसले में 1-4 से हार गयीं। दूसरी वरीय जापानी खिलाड़ी के खिलाफ मीनाक्षी की शुरुआती धोमी रही जबकि प्रतिद्वंद्वी मुक्केबाज ने इस भारतीय की मुस्ती का पूरा फायदा उठाया और पांच में से चार जज का फैसला अपने पक्ष में कराया। दूसरे दौर में भी मीनाक्षी सटीक मुकें नहीं जड़ सकीं जबकि जापानी मुक्केबाज ने सही जगह पर मुकें जड़कर अंक बढ़ाए और अच्छा बचाव किया। अंतिम तीन मिनिट में मीनाक्षी ने शानदार वापसी की और मुकें के अच्छे तालमेल से अंक जुटाये जिससे उन्हें 1-4 से हार मिली।

चिकित्सा-इंजीनियरिंग शिक्षा तमिल में शुरू करना चाहिए : शाह

चेन्नई, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। मातृभाषा में चिकित्सा और इंजीनियरिंग शिक्षा की कालांतर करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रम शुरू करने को भाषा के लिए एक महान योगदान बताया।

सीमेंट प्रमुख इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के प्लेटीनम जुबिली समारोह में बोलते हुए, शाह ने कहा कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग शिक्षा तमिल में होनी चाहिए और राज्य सरकार को इसे शुरू करना चाहिए।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि छात्रों के लिए अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करना आसान होगा और वे अपनी भाषा में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) भी कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है और पूरे भारत को इस पर गर्व है।

रक्षा गलियारे जैसी विभिन्न

परियोजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए, शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कहा कि पिछले आठ वर्षों के दौरान राज्य और केंद्रीय अनुदान के लिए कर हस्तांतरण कई गुना बढ़ गया है।

शाह के मुताबिक, अगर कोई कंपनी 75 साल से अस्तित्व में है तो यह दर्शाता है कि वह उस सेगमेंट में अग्रणी है।

कंपनी को शीर्ष पर ले जाने के लिए इंडिया सीमेंट के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एन श्रीनिवासन की प्रशंसा करते हुए शाह ने यह भी कहा कि जब इंडिया सीमेंट्स के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अखिल भारतीय चैस संघ (एआईसीएफ) का नेतृत्व कर रहे थे तो वह गुजरात राज्य चैस संघ के अध्यक्ष थे।

शाह गुजरात क्रिकेट संघ के पदाधिकारी भी थे जब श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष थे।



आर्थिक मोर्चे पर, शाह ने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अच्छी तरह से बढ़ रहा है और मॉर्गन स्टेनली का हवाला दिया जिसने कहा था कि देश 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

देश में राजनीतिक स्थिरता के साथ, शाह ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि भारत

अंधेरे शिक्तिज में एक उज्ज्वल स्थान है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा कि 18वीं सदी तक भारत दुनिया का आर्थिक महाशक्ति था, इसका गौरवशाली इतिहास मिटा दिया गया। इसका कारण यह था कि भारत में स्टील बनाना एक कठिन उद्योग की तरह था और उस समय वर्तमान आंध्र प्रदेश क्षेत्र में 10,000 से अधिक स्मेल्टर थे जो बेहतर गुणवत्ता वाले स्टील बना रहे थे।

रवि ने कहा कि शेफील्ड ने

इस प्रक्रिया को सीखने के लिए अपनी टीम भारत भेजी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योग को खत्म कर दिया, फिर शेफील्ड समृद्ध हुआ। रवि ने कहा कि पिछले 200 वर्षों में भारतीय उद्योग के साथ क्या हुआ था, इस पर विचार करना होगा। भारत की आजादी के बाद लाइसेंस परमिट राज ने विकास में बाधा डाली। उनके मुताबिक मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है।

कानून दमन का साधन न बने, यह तय करना सभी नीति निर्धारकों की जिम्मेदारी : सीजेआई

नई दिल्ली, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून दमन का साधन नहीं बल्कि न्याय का साधन बना रहे, यह तय करना केवल न्यायाधीशों का नहीं, बल्कि सभी नीति निर्धारकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकों से उम्मीदें रखना बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें संस्थानों के रूप में अदालतों की सीमाओं और उनकी क्षमता को समझने की भी जरूरत है।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कभी-कभी कानून और न्याय आवश्यक रूप से एक ही रेखा पर प्रक्षेपवक्र का पालन नहीं करते हैं। कानून न्याय का एक साधन हो सकता है, लेकिन कानून उत्पीड़न का एक साधन भी हो सकता है। हम जानते हैं कि कैसे औपनिवेशिक काल में वही कानून प्रताड़ना के साधन बने थे। तब के समय की कानून की किताबें आज उत्पीड़न के साधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम एक



नागरिक के रूप में यह कैसे तय करते हैं कि कानून न्याय का साधन बन जाए और कानून उत्पीड़न का साधन न बने। ऐसे में कानून को न्याय का साधन बने रहने देने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही सभी निर्णय निर्माताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

सीजेआई ने आगे कहा कि जो चीज लंबे समय तक न्यायिक संस्थानों को बनाए रखती है, वह करुणा की भावना, सहानुभूति की भावना और नागरिकों के प्रति जवाबदेही की क्षमता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सलाह देते हुए कहा कि जब आप अपने सिस्टम में अनुसूची आवाजें सुनने की क्षमता रखते हैं और फिर देखते हैं कि कानून और न्याय के बीच संतुलन कहाँ है। ऐसा करके आप वास्तव

में एक न्यायाधीश के रूप में अपना मिशन पूरा कर सकते हैं।

इस दौरान उन्होंने न्यायाधीशों के सामने आने वाली मुसीबतों का भी जिक्र किया। सीजेआई ने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया ने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को पेश किया है क्योंकि एक न्यायाधीश द्वारा अदालत में कहे गए हर छोटे शब्द की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग होती है।

इस तरह एक न्यायाधीश के रूप में आपका लगातार मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अदालतों में न्याय करने की प्रक्रिया संवाद है। अदालत में वकीलों और न्यायाधीशों के बीच मुक्त प्रवाह वाली बातचीत होती है, जो सच्चाई को उजागर करने के प्रयास में होती है।

किसानों को दोषी नहीं ठहरा सकते, चार राज्य सरकारों की विफलता जिम्मेदार : एनएचआरसी

नई दिल्ली, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने वायु प्रदूषण पर अहम बैठक की। इस दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों ने भी अपनी बात रखी। सभी का पक्ष सुनने के बाद दिल्ली-एनसीआर में एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर एनएचआरसी ने कहा कि किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए चार राज्य सरकारों की विफलता जिम्मेदार है। यही वजह है कि पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं।

प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली और तीन पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों की प्रतिक्रिया सुनने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शनिवार को कहा कि किसान 'मजबूत' के तहत पराली जला रहे हैं और यह

सरकार की 'विफलता' के कारण है।

दिल्ली-एनसीआर में बड़े प्रदूषण से चिंतित एनएचआरसी ने हाल ही में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को इस मामले पर चर्चा के लिए 10 नवंबर को पेश होने को कहा था। एनएचआरसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आयोग ने संबंधित राज्यों और दिल्ली सरकार की प्रतिक्रियाओं और उस पर विचार-विमर्श के बाद यह राय दी है कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं।

आयोग ने कहा कि राज्य सरकारों को उन पराली से छुटकारा पाने के लिए हार्वेस्टिंग मशीनें उपलब्ध करानी पड़ती हैं, लेकिन वे पर्याप्त संख्या में आवश्यक मशीनें और अन्य उपाय उपलब्ध कराने में

विफल रही हैं। परिणामस्वरूप किसान पराली जलाने के लिए मजबूर हैं, जिससे प्रदूषण होता है।

आयोग ने कहा कि कोई भी राज्य किसानों को पराली जलाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, बल्कि इन चारों सरकारों की विफलता के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में पराली जलायी जा रही है एवं हवा में इतना प्रदूषण फैल रहा है।

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर को फिर से या तो व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड में उपस्थित रहने के लिए कहा है।

इससे पहले उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया या हलफनामे चार दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है।

जिसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है वे ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे : थरूर

नई दिल्ली, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है वे ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि यहां हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2022 के आखिरी दिन असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि कांग्रेस के 'कुछ अच्छे लोग' भाजपा में शामिल होंगे। हिमंत विश्व शर्मा हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर कटाक्ष कर रहे थे।

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड्गे और शशि थरूर दो प्रमुख उम्मीदवार मैदान में थे। जीत भले ही खड्गे की हुई लेकिन थरूर को एक हजार से ज्यादा वोट मिले। इसी पर कटाक्ष करते हुए असम सीएम ने कहा कि कांग्रेस में थरूर को वोट करने वाले जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। अब असम सीएम के बयान पर शशि थरूर का रिएक्शन आया है।

समाचार एजेंसी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में शशि थरूर ने कहा, 'हिम्मत दिखाने वाले कभी भाजपा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है, वे ऐसा करने के लिए लालायित हो सकते हैं।'

बता दें कि असम के सीएम ने मल्लिकार्जुन खड्गे को पार्टी अध्यक्ष बनाने पर अपनी पूर्व पार्टी कांग्रेस



की आलोचना की। शर्मा ने कहा कि यदि शशि थरूर चुनाव जीते होते तो वे कहते कि कांग्रेस में लोकतंत्र की वापसी हो गई है।

इसी दौरान हिमंत शर्मा ने कहा कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस के

जिन 1000 लोगों ने शशि थरूर के पक्ष में मतदान किया, वे छह महीने या एक साल में भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक भाजपा देश में हर जगह मौजूद होगी।

भाजपा चुनाव आयोग की स्वतंत्रता नष्ट कर रही: महबूबा

श्रीनगर, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर चुनाव आयोग को इस हद तक बर्बाद करने का आरोप लगाया कि वह अब स्वतंत्र निकाय नहीं रहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा का विस्तार (शाखा) बन गया है। उन्होंने कहा, भाजपा उससे जो कुछ कहेगी, वह वही करेगा। मुफ्ती ने अनंतनाग जिले के खैरम क्षेत्र में संवाददाताओं से कहा, चुनाव आयोग को इस हद तक कमजोर कर दिया गया है कि वह स्वतंत्र निकाय नहीं रहा, जिसपर देश को गर्व था। हमारे चुनाव आयुक्तों को चुनाव कराने में विशेषज्ञ सलाह के लिए अन्य देश आमंत्रित करते थे।

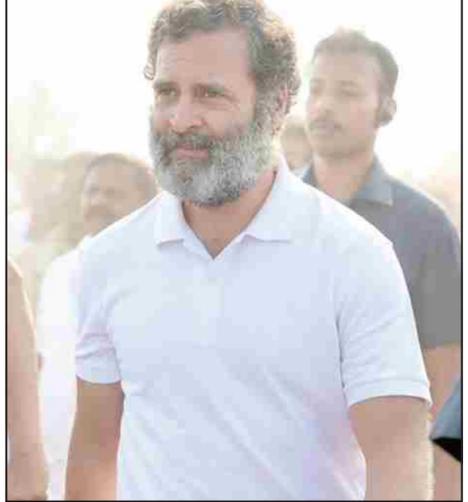
उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कानूनों का उल्लंघन करने के बाद भी चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेतृत्व ने धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार किया। मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं कैसे कह सकती हूँ कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे। वह चुनाव आयोग तय करेगा और जब भाजपा आयोग से कहेगी तब वह चुनाव की घोषणा करेगा।

शासन के मुद्दे पर मुफ्ती ने कहा कि वर्तमान सरकार सब कुछ पलटने पर तुली है। उन्होंने कहा, कश्मीरी पंडितों को देखिए जो पिछले कई महीनों से जम्मू में डेरा डाले हुए हैं। वे मांग कर रहे हैं कि जब तक कश्मीर में स्थिति सुधर नहीं जाती है, तब तक उन्हें जम्मू भेज दिया। लेकिन सरकार कभी उनका वेतन रोक रही है तो कभी राशन।

पीडीपी अध्यक्ष ने दावा किया कि भाजपा चुनाव की खातिर कश्मीरी पंडितों की पीड़ा का फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा, उसे किसी की परवाह नहीं है, चाहे कश्मीरी पंडित हो या कोई और। वह बस चुनाव जीतना चाहती है।

भारत को बांट नहीं जा सकता : राहुल



नई दिल्ली, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को फिर से शुरू हो गई। 166वें दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में हिमाली के शेवाला गांव से यात्रा शुरू हुई। आज की यात्रा आरती गांव, पारडी मोड़ बस स्टैंड और कलामनुरी जिला परिषद हाई स्कूल मैदान से होकर गुजरी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का संदेश यह है कि भारत को बांट नहीं जा सकता और नफरत नहीं फैलाई जा सकती। यह यात्रा श्रीनगर में समाप्त होगी और हम यह संदेश देंगे कि भारत को बांट नहीं जा सकता और नफरत

नहीं फैलाई जा सकती। यात्रा का यही उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि भारत में तीन-चार अरबपति हैं। वे जो चाहे कर सकते हैं। उन्हें जो भी व्यवसाय चाहिए, वे कर सकते हैं चाहे हवाई अड्डा, बंदरगाह, सड़क, बुनियादी ढांचा, दूरसंचार या बैंकिंग हो, लेकिन देश के युवा नौकरी चाहते हैं तो उन्हें यह नहीं मिलती।

कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इससे पहले यह यात्रा महाराष्ट्र के पांच जिलों में 382 किमी की दूरी तय करेगी।

गुजरात में भी भाजपा के लिए चुनौती बन रहे बागी, डैमेज कंट्रोल में जुटे दिग्गज

अहमदाबाद, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए बागी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी का एक मौजूदा और चार पूर्व विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की धमकी दी है।

भाजपा के कुछ अन्य असंतुष्ट नेताओं ने भी बगावत के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपने समर्थकों से परामर्श करने के बाद अगला कदम उठाएंगे। इस बीच भाजपा के पूर्व विधायक हर्षद वसावा ने शुक्रवार को नंदोड (अनुसूचित जनजाति आरक्षित) सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया।

उल्लेखनीय है कि हर्षद वसावा भाजपा की गुजरात इकाई के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने 2002 से 2007 और 2007 से 2012 तक पूर्ववर्ती राजपीपला सीट का प्रतिनिधित्व किया था।

नर्मदा जिले की नंदोड सीट पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट से भाजपा ने डॉ दर्शन देशमुख को उतारा है। इस घोषणा से नाखुश हर्षद वसावा ने भाजपा

में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और शुक्रवार को नंदोड सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

वसावा ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यहां असली भाजपा और नकली भाजपा में लड़ाई है। हम उन लोगों को बेनकाब करेंगे, जिन्होंने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया है। मैंने अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है। इस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैंने 2002 से 2012 के बीच विधायक के रूप में कितना काम किया है।

वडोदरा जिले में भी एक मौजूदा और दो पूर्व भाजपा विधायक टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज हैं। वाघोडिया से छह बार के विधायक मधु श्रीवास्तव ने टिकट नहीं दिए जाने के बाद कहा कि यदि उनके समर्थक चाहते हैं तो वह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने इस सीट से अश्विन पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है।

वडोदरा जिले की पादरा सीट से भाजपा के एक अन्य पूर्व विधायक दिनेश पटेल उर्फ दीनू मामा ने भी कहा है कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने इस सीट से चैतन्यसिंह

रामपुर और आजमगढ़ वाली गलती नहीं करेंगे अखिलेश, डिंपल के लिए झोंकेंगे पूरी ताकत

लखनऊ, 12 नवम्बर (एजेन्सी)। मैनपुरी सीट से सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव को जिताने के लिए सपा पूरी ताकत से लड़गी। पत्नी डिंपल के लिए अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर और आजमगढ़ वाली गलतियों को नहीं दोहराएंगे। दरअसल मैनपुरी का अभेद्य दुर्ग भाजपा भेद न सके इसके लिए अखिलेश हर स्तर पर सावधानी बरत रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ में सपा की हार की अखिलेश के चुनाव प्रचार न करने की वजह बताई गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।

अखिलेश यादव और संगठन के बड़े नेता इस बार चुनावी प्रचार भी करेंगे और डिंपल को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। रामपुर और आजमगढ़ में मिली हार पर अखिलेश यादव ने बताया था कि वह क्यों चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। उन्होंने कहा, पार्टी पदाधिकारियों ने मना किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मतदाताओं को निकलने ही नहीं दिया, पैसा बांटा गया और टुक से शराब भी भेजी गई।



उन्होंने बताया कि मुझे भरोसा दिया गया था कि मेरे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे अतिविश्वास में आए अखिलेश इस बार पिछली बार तरह गलती नहीं दोहराएंगे। पत्नी डिंपल और सपा की साख बचाने के लिए अखिलेश यादव मैनपुरी में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। परिवार में कोई फूट नजर न आए इसको लेकर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप को चुनाव प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर एक मंच पर खड़ा करेंगे।

पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से उतारने से पहले अखिलेश ने यहां जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की है। दरअसल मैनपुरी सीट पर यादव के बाद सबसे अधिक शाक्य मतदाता हैं इसलिए अखिलेश ने पूर्व

जाला को टिकट दिया है। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। करजन में भाजपा के पूर्व विधायक सतीश पटेल मौजूदा विधायक अक्षय पटेल को टिकट देने के फैसले से नाराज बताए जाते हैं।

इस बीच, जूनागढ़ की केशोद सीट से भाजपा के पूर्व विधायक अरविंद लडानी ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी द्वारा मौजूदा विधायक देवभाई मालम को टिकट दिए जाने के कारण वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने अब तक कुल 182 विधानसभा क्षेत्रों में से 166 क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।

बागियों के गुस्से को शांत करने के लिए पार्टी की राज्य इकाई के नेता सक्रिय हो गए हैं। स्थिति को संभालने के लिए भाजपा की राज्य इकाई के महासचिव भार्गव भट्ट और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने वडोदरा का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भार्गव भट्ट ने विश्वास जताया कि भाजपा वडोदरा की सभी सीट पर जीत हासिल करेगी। मालूम हो कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक और पांच दिसंबर को दो चरणों में मतदान होगा।